[2023] 11 एस**.** सी**.** आर **1005:2023** आई**.** एन**.** एस**.** सी**. 793**

मुकदमों का विवरण

मुन्ना पांडे बनाम।

बिहार राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1271-1272) सितंबर 04,2023

[बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** बी**.** पारदीवाला और प्रशांत कुमार मिश्रा**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और मौत की सजा को स्वीकार करने में गलती की है, यह दंडनीय यू/एस है।302, 376, आई. पी. सी. और एस.4, पूरी जाँच में गंभीर खामियों के बावजूद पॉक्सो अधिनियम, 2012।

दंड संहिता**, 1860-**एस**.** एस**.302, 376 –** यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम**, 2012 -**धारा **4-**जाँच में गंभीर खामियाँ**,** दोषसिद्धि और मृत्युदंड**-**स्वामित्वः

आयोजित किया गयाःs.162, सी. आर. पी. सी. एक न्यायाधीश को पुलिस जांच के रिकॉर्ड को देखने से नहीं रोकता है-एक 10 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या का मामला होने के नाते और सबूत संदेह से मुक्त नहीं होने के कारण, ट्रायल जज को महत्वपूर्ण सामग्री से परिचित होना चाहिए था और यह भी कि पुलिस जांच के दौरान अभियोजन पक्ष के एकमात्र महत्वपूर्ण गवाहों ने क्या कहा था-एस में कुछ भी नहीं है।162, सी. आर. पी. सी. जो एक विचारण न्यायाधीश को आरोपपत्र के कागजातों को स्वतः देखने से रोकता है और स्वयं उस व्यक्ति के बयान का उपयोग करने से रोकता है जो पुलिस द्वारा जांच किए गए व्यक्ति के बयान का खंडन करने के उद्देश्य से दर्ज किया गया है जब वह अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में राज्य के पक्ष में सबूत देता है-न्यायाधीश ऐसा कर सकता है या वह आरोपी के वकील को रिकॉर्ड किए गए बयान को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है-पुलिस के सामने गवाहों का मामला यह था कि यह सह-आरोपी था जो दुर्भाग्यपूर्ण दिन पीड़ित के घर आया था और उसे टीवी देखने के लिए अपने घर ले गया था-सभी बयानों से आगे पता चलता है कि यह सह-आरोपी था जो दरवाजा बंद करते हुए पाया गया था जब गवाहों ने उसके साथ पीड़ित के ठिकाने के बारे में पूछताछ की थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बचाव पक्ष के वकील, न लोक अभियोजक, न ही विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी मामले के उपरोक्त पहलू पर गौर करने और सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करने के बारे में नहीं सोचा-विचारण न्यायालय का पीठासीन अधिकारी मूक दर्शक बना रहा-पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य था कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन गवाहों से प्रासंगिक प्रश्न पूछे।165, साक्ष्य अधिनियम-विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-संदर्भ यू/एस पर निर्णय लेने के लिए मामला उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया।366, सी. आर. पी. सी. अभियोजन पक्ष के गवाहों के मौखिक साक्ष्य-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस. से सामने आने वाले भौतिक चूक के रूप में प्रमुख विरोधाभासों को साबित नहीं करने में बचाव पक्ष की ओर से गंभीर खामियों को ध्यान में रखते हुए।162, 366 – साक्ष्य अधिनियम, 1872 -s.165।[पारस 39,40,43,47 और 73]

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 -s.162-**प्रावधान**-**उसमें उल्लिखित **'**उद्देश्य**':**

आयोजित किया गयाःs.162 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जांच के दौरान पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, चाहे वह दर्ज किया गया हो या नहीं, इस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि धारा के पहले परंतुक में प्रावधान किया गया है-प्रथम परंतुक में कहा गया है कि जब कोई गवाह, जिसका बयान पुलिस द्वारा सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में कम कर दिया गया है, उसे जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है, तो अदालत की अनुमति से आरोपी एस. द्वारा प्रदान किए गए तरीके से गवाहों का खंडन कर सकता है।145, साक्ष्य अधिनियम-परंतुक में उल्लिखित उद्देश्य ऐसे गवाह द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए पिछले बयान का उपयोग करके अदालत में

अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा राज्य के पक्ष में दिए गए साक्ष्य का खंडन करना है-उद्देश्य राज्य के लिए एक गवाह द्वारा अभियोजन पक्ष के पक्ष में दिए गए साक्ष्य को बदनाम करना है-धारा इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए बयान के उपयोग को प्रतिबंधित करती है-यह नहीं कहता है कि बयान का उपयोग केवल आरोपी के अनुरोध पर किया जा सकता है-एस के पहले भाग में लगाई गई सीमा या प्रतिबंध।162 इस उद्देश्य से संबंधित है जिसके लिए बयान का उपयोग किया जा सकता है; यह उस प्रक्रिया से संबंधित नहीं है जिसे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाया जा सकता है-सीमित उद्देश्य को निर्धारित करने वाले परंतुक में उस तरीके का भी उल्लेख है जिसमें एक आरोपी व्यक्ति पुलिस को दिए गए अपने पिछले बयान के साथ गवाह का खंडन कर सकता है, लेकिन यह किसी अन्य तरीके से उस शक्ति को प्रभावित नहीं करता है जो अदालत में दस्तावेजों को देखने या गवाहों से सवाल करने के लिए निहित है-साक्ष्य अधिनियम, 1872 -s.165।[पैरा 46] 1007

अभ्यास और प्रक्रिया**-**आपराधिक कानून**-**पीठासीन न्यायाधीश का कर्तव्य**-**साक्ष्य अधिनियम**, 1872 -s.165:**

आयोजित किया गयाःकई सत्र मामलों में जब न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई अधिवक्ता उपस्थित होता है और विशेष रूप से जब न्यायालय की प्रक्रिया का अधिक अनुभव नहीं रखने वाले एक कनिष्ठ अधिवक्ता को किसी अभियुक्त व्यक्ति का बचाव करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो पीठासीन न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह एस के वैधानिक प्रावधानों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करे।145, साक्ष्य अधिनियम-किसी भी न्यायालय को किसी गवाह को लिखित रूप में पिछले बयान के संदर्भ में खंडन करने या लिखित रूप में कम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जब तक कि एस में निर्धारित प्रक्रिया न हो।145, साक्ष्य अधिनियम का पालन किया गया है-यह संभव है कि यदि गवाह का ध्यान इन भागों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिनके संदर्भ में उसका खंडन करने का प्रस्ताव किया गया है, तो वह पूरी तरह से संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में सक्षम हो सकता है और उस स्थिति में पिछले बयान का हिस्सा जो अन्यथा विरोधाभासी होगा, अब गवाह की गवाही का खंडन या चुनौती देने के लिए नहीं जाएगा-वर्तमान जैसे मामले में, जहां अदालत में दिया गया सबूत उन व्यक्तियों को निहित करता है जिनका उल्लेख प्राथमिकी या पुलिस बयानों में नहीं किया गया है, यह हमेशा सलाह दी जाती है और विचारण न्यायाधीश के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वह पुलिस दस्तावेजों को देखे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या गवाहों द्वारा फंसाये गए व्यक्तियों को उनके द्वारा जांच के दौरान फंसाया गया था।[पैरा 47 और 48]

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 -**धारा **53 (1), 53** ए**-**चिकित्सा जांच**-**महत्व**-**परिवेशी साक्ष्य**-**बलात्कार पीड़ित की मृत्युः

आयोजित किया गयाःएस. 53 (1) उप-निरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी जांच करने का अनुरोध करने के लिए सक्षम बनाता है, जो उन तथ्यों का पता लगाने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक है जो ऐसे साक्ष्य का समर्थन कर सकते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को ऐसी प्रकृति का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होते हैं कि उसके व्यक्ति की जांच से अपराध करने के बारे में सबूत मिल जाएगा-2005 के संशोधन अधिनियम 25 द्वारा, एक नया स्पष्टीकरण यू/एस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।53, मूल स्पष्टीकरण के स्थान पर-एक नए स्पष्टीकरण यू/एस के प्रतिस्थापन के साथ।53, 2005 के अधिनियम 25 में एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है। s.53A-एक अभियुक्त की चिकित्सा जांच उन मामलों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है जहां बलात्कार की पीड़ित की मृत्यु हो गई है और केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य-दंड संहिता, 1860-एस. एस. द्वारा अपराध स्थापित करने की मांग की जाती है।302, 376 – दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005।[पारस 25-27 और 29]

मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य 1008 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 -s.313-**अतिरिक्त परिस्थितियों पर भरोसा किया गया**,** अपीलार्थी के सामने नहीं रखा गया**-**अनुचितताः

आयोजित किया गयाःअपीलार्थी-दोषी का अगला बयान यू/एस दर्ज किया गया था।313 – जिस तरह से निचली अदालत ने इसे दर्ज किया, उसे देखना चौंकाने वाला था-कुल मिलाकर, अपीलार्थी से चार प्रश्न पूछे गए ताकि वह कथित अपराध में अपनी संलिप्तता की ओर इशारा करने वाली दोषपूर्ण परिस्थितियों की व्याख्या कर सके-हालाँकि, अपीलार्थी को कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए, निचली अदालत ने उन अतिरिक्त परिस्थितियों पर गौर किया जिनमें से किसी को भी अपीलार्थी के सामने नहीं रखा गया था ताकि वह इसका उचित स्पष्टीकरण दे सके।[पैरा 32]

साक्ष्य अधिनियम**, 1872-ss.145, 161 –** बचाव पक्ष के वकील**,** लोक अभियोजक का कर्तव्यः

आयोजित किया गया:बचाव पक्ष के वकील का कर्तव्य था कि वह गवाहों का उनके पुलिस बयानों के साथ सामना करे ताकि भौतिक चूक के रूप में विरोधाभासों को साबित किया जा सके और उन्हें रिकॉर्ड पर लाया जा सके-बचाव पक्ष के वकील को पता नहीं था कि किसी गवाह को उसके पुलिस बयानों के साथ कैसे विरोधाभासी बनाया जाए।145, साक्ष्य अधिनियम-लोक अभियोजक की ओर से चूक भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है-लोक अभियोजक को पता था कि गवाह पुलिस के सामने दर्ज अपने बयानों में जो कुछ कहा था, उसके विपरीत कुछ बयान दे रहे थे।161 – यह उसका कर्तव्य था कि वह गवाहों के ध्यान में लाए और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किए बिना भी उनका सामना करे-यदि गवाह का सामना बयान के उस हिस्से से नहीं किया गया था जिसके साथ बचाव पक्ष उसका खंडन करना चाहता था, तो अदालत स्वतः ही पुलिस को दिए गए बयानों का उपयोग नहीं कर सकती है जो अनुपालन में साबित नहीं हुए हैं।145, साक्ष्य अधिनियम-इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी प्रमुख विरोधाभासों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार भौतिक चूक के रूप में साबित किया जाए।145, साक्ष्य अधिनियम और उन्हें अभिलेख पर लाना-ऐसा करना बचाव पक्ष के वकील का कर्तव्य है।[पैरा 41 और 50]

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973-**अध्याय **XXVIII-ss.366- 371;** अध्याय **21-**एस**.** एस**.372-394 –** कन्फ़र्मेशन मामलों में उच्च न्यायालय की भूमिका और कर्तव्यः

आयोजित किया गया:व्यक्ति को दोषमुक्त करने की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की ओर से उसकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली कोई ठोस अपील किए बिना भी किया जा सकता है-उस हद तक, अध्याय XXVIII के तहत कार्यवाही जो "कारावास के लिए मौत की सजा प्रस्तुत करने" से संबंधित है।

1009

मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य 1010

यह मुकदमे की निरंतरता में एक कार्यवाही है।367, 368 उच्च न्यायालय को आगे की जांच का निर्देश देने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार देता है और उच्च न्यायालय किसी मामले में अभियुक्त व्यक्ति को बरी भी कर सकता है-अध्याय का दायरा व्यापक है-अध्याय XXIX "अपील" से संबंधित है -s.391 अपीलीय न्यायालय को आगे साक्ष्य लेने या इस तरह के आगे साक्ष्य लेने का निर्देश देने का भी अधिकार देता है -s.386 तब अपीलीय न्यायालय की शक्तियों की गणना करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "निर्णय और सजा को उलटने और अभियुक्त को बरी या आरोपमुक्त करने की शक्ति शामिल है, या उसे ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा फिर से मुकदमा चलाने का आदेश देना या मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करना"-अपीलीय न्यायालय की शक्तियां समान रूप से व्यापक हैं-वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय अध्याय XXVIII और XXIX, सी. आर. पी. सी.-एस. दोनों शक्तियों का प्रयोग कर रहा था।367, 368 यह स्पष्ट करें कि निर्देश से निपटने में उच्च न्यायालय का कर्तव्य केवल यह देखना नहीं है कि सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश सही है या नहीं, बल्कि अपने लिए मामले की जांच करना है और यहां तक कि दोषी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता का पता लगाने के लिए आगे की जांच या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देना है।[पैरा 58 और 59]

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973-**एसएस।**367, 368** और उसके लिए परंतुक**-**उच्च न्यायालय का कर्तव्य यू/एस।**367:**

आयोजित किया गया:एस के परंतुक के तहत।368, जब तक अपील को प्राथमिकता देने के लिए अनुमत अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, या, यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई अपील प्रस्तुत की जाती है, तब तक जब तक कि ऐसी अपील का निपटारा नहीं किया जाता है, ताकि, यदि कोई अपील किसी दोषी कैदी के नेतृत्व में की जाती है, तो उस अपील का निपटारा मृत्यु की सजा को स्वीकार करने वाले संदर्भ में कोई आदेश दिए जाने से पहले किया जाना चाहिए-हालाँकि, ऐसी अपील का निपटारा करने में, यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए।367 – उसे अपने लिए अपील रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए, इस विचार पर पहुंचना चाहिए कि आगे की जांच या अतिरिक्त साक्ष्य लेना वांछनीय है या नहीं, और फिर रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या दोषी कैदी की दोषसिद्धि न्यायसंगत है और मौत की सजा को स्वीकार किया जाना चाहिए।[पैरा 59]

आपराधिक कानून**-**आपराधिक न्याय प्रणाली**-**अभियोगकारी**/**प्रतिकूल प्रणालीः

आयोजित किया गया:आपराधिक न्याय के वितरण के लिए**,** भारत सामान्य कानून की अभियोगात्मक या प्रतिकूल प्रणाली का पालन करता है**-**आरोपात्मक या

[2023] 11 एस सी आर।

प्रतिकूल प्रणाली, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है; अभियोजन और बचाव प्रत्येक अपना मामला रखते हैं; न्यायाधीश एक निष्पक्ष अंपायर के रूप में कार्य करता है और एक तटस्थ अंपायर के रूप में कार्य करते हुए देखता है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम है या नहीं।[पैरा 66]

भारत का संविधान**-**अनुच्छेद **21-**स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई**,** एक अनिवार्य **-**

गैरः

आयोजित किया गयाःस्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई अनुच्छेद 21 की अनिवार्यता है-यदि आपराधिक सुनवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, तो एक न्यायाधीश की न्यायिक निष्पक्षता और न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास हिल जाएगा-निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करना आरोपी के लिए उतना ही अन्याय है जितना कि पीड़ित और समाज के लिए-किसी भी मुकदमे को निष्पक्ष सुनवाई के रूप में तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि मुकदमे का संचालन करने वाला एक निष्पक्ष न्यायाधीश, एक ईमानदार, सक्षम और निष्पक्ष बचाव वकील और समान रूप से ईमानदार, सक्षम और निष्पक्ष लोक अभियोजक न हो-एक निष्पक्ष सुनवाई में अभियोजक को आरोपी के अपराध को साबित करने का निष्पक्ष और उचित अवसर और आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर शामिल है।[पैरा 67]

आपराधिक कानून**-**आपराधिक न्याय प्रणाली**-**न्याय के वितरण में एक न्यायाधीश की भूमिका**-**चर्चा की गई।**[**पैरा **53,54,68** और **70]**

समितियाँ**-**न्यायिक सुधारों पर मलिमथ समिति**-**सच्चाई की खोज करने के लिए न्यायालयों का कर्तव्य**-**समिति के अवलोकन**-**पर चर्चा की गई।

[पैरा 69]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

जुम्मन बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 469:राम शंकर सिंह @राम शंकर रॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1239:[1962] पूरक।एस. सी. आर. 49; भूपेन्द्र सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 1438:[1968] एससीआर 404; छोटकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) 6 एससीसी 742; तारा

सिंह बनाम राज्य आकाशवाणी 1951 एस. सी. 441:[1951] एससीआर 729; वी. के. मिश्रा बनाम उत्तराखंड राज्य, (2015) 9 एससीसी 588:[2015] 8 एससीआर 1; रघुनाथन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 186: [1974] 3 एस. सी. आर. 92, दांडू लक्ष्मी रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य (1999) 7 एस. सी. सी. 69:[1999] 1 पूरक।एस. सी. आर. 535; राजस्थान राज्य बनाम अनी @हनीफ और अन्य। (1997) 6 एससीसी 162:[1997] 1 एससीआर 199; राम चंदर बनाम हरियाणा राज्य (1981) 3 एससीसी 191:[1981] 3 एस. सी. आर. 12; मसाला बनाम राज्य

उत्तर प्रदेश (1964) 8 एससीआर 133; कुणाल मजूमदार बनाम राजस्थान राज्य (2012) 9

एससीसी 320:[2012] 8 एससीआर 706-पर निर्भर।

1011

मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य 1012

सत्र न्यायाधीश, नेल्लोर बनाम इंथा रमण रेड्डी 1972 Cri.L.J. 1485

– संदर्भित किया गया।जोन्स बनाम राष्ट्रीय कोयला बोर्ड 1957 (2) सभी ई. आर. 155 (सी. ए.)-निर्दिष्ट।सरकार (1999,15 वां पृष्ठ 2319 आदि।); फिपसन (साक्ष्य, 1999,15 वाँ संस्करण, पैरा 1.21)-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2018 की आपराधिक अपील संख्या 1271-1272।

2017 के डी. आर. सं. 4 और 2017 के सी. आर. ए. डी. बी. सं. 358 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

रूपः

डॉ. आदित्य सोंधी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री ऐश्वर्या सारंगा, सुश्री मेघना टी. एम., सुश्री हरिनी रघुपति, कबीर दीक्षित, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

समीर अली खान, प्रांजल शर्मा, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.:**

“एक निष्पक्ष परीक्षण वह है जिसमें साक्ष्य के नियमों का सम्मान किया जाता है, अभियुक्त के पास सक्षम वकील होता है, और न्यायाधीश उचित अदालत कक्ष प्रक्रियाओं को लागू करता है-एक ऐसा परीक्षण जिसमें प्रत्येक धारणा को चुनौती दी जा सकती है।"

– हैरी ब्राउन 1.ये अपीलें "एक्स" नामक 10 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए मौत की सजा पाए एक दोषी आरोपी के कहने पर की गई हैं और 2017 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 358 के साथ 2017 की मृत्यु संदर्भ संख्या 4 में पटना में उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी दोषी के नेतृत्व में आपराधिक अपील को खारिज कर दिया था और इस तरह दोषसिद्धि और मौत की सजा के फैसले को स्वीकार किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I, भागलपुर द्वारा 2015 के सत्र परीक्षण संख्या 581 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पारित किया गया।2. अभियोजन पक्ष के मामले के संबंध में एक उचित विचार देने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने न केवल अभियुक्त के नेतृत्व में अपील की थी, बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी. आर. पी. सी.) की धारा 366 के तहत मृत्युदंड की सजा को स्वीकार करने के लिए सत्र न्यायालय द्वारा एक संदर्भ भी दिया था।बार-बार इस न्यायालय ने बताया है कि मृत्युदंड की सजा को स्वीकार करने के लिए एक संदर्भ पर, उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 और 368 के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए बाध्य है। इन धाराओं के तहत उच्च न्यायालय को न केवल यह देखना चाहिए कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है या नहीं, बल्कि यह सत्र न्यायालय के मूल्यांकन और उस साक्ष्य के मूल्यांकन के अलावा और स्वतंत्र रूप से पूरे साक्ष्य की जांच करने के लिए बाध्य है। निर्णयों की लंबी कतार से, जिन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया है, यह जुम्मन बनाम में निर्णयों का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त होगा।

पंजाब राज्य**,** ए**.** आई**.** आर**. 1957** एस**.** सी**. 469;** राम शंकर सिंह **@**राम शंकर रॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**,** ए**.** आई**.** आर**. 1962** एस**.** सी**. 1239;** और भूपेंद्र सिंह बनाम।

पंजाब राज्य**,** ए**.** आई**.** आर **1968** एस**.** सी**. 1438**।

मामले के तथ्य

3. उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित फैसले में दर्ज मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 01.06.2015 पर लगभग 12 बजेः45 प्रधानमंत्री, अरविंद साह की पत्नी किरण देवी (पीडब्लू. 2) की फरदबेयान और पीड़ित की मां को Police-cum-S.H.O की उप-निरीक्षक द्वारा दर्ज किया गया था। सबौर पुलिस स्टेशन की रीता कुमारी।फर्दबेयान नवल किशोर ओझा उर्फ फुचान पांडे के घर में रिकॉर्ड किया गया था।नवल किशोर ओझा उर्फ फुचन पांडे अपीलार्थी का अपना भाई है और उक्त घर में दो कमरे थे और एक कमरा, जहाँ से शव बरामद किया गया

था, अपीलार्थी के कब्जे में था।फरदबेयान में, मुखबिर/पीडब्लू. 2 ने कहा कि पिछली तारीख यानी 31.05.2015 पर, वह गाँव जमुनिया परबत्ता में अपनी दिवंगत बहन शकीला देवी के घर पर थीं।उसी तारीख को लगभग 12 बजेः

दोपहर में, उनकी बड़ी बेटी प्रिया कुमारी (पीडब्लू. 3) ने उन्हें टेलीफोन पर सूचित किया कि उनकी छोटी बहन (पीड़ित) लापता है।इसके बाद, वह तुरंत सबौर चली गईं।सबौर गाँव में अपने घर पहुंचने के बाद, उसकी बड़ी बेटी प्रिया ने उसे सूचित किया कि पीड़ित मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के घर टेलीविजन देखने गई थी।जब वह 11 बजे तक नहीं लौटीः00 एएम, उसके बाद ही, उसने (प्रिया) मुखबिर को सूचित किया।जब मुखबिर अपनी बेटी की तलाश में मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के घर गया, तो उसने पाया कि मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) का घर बंद था।इसके बाद, कुछ ग्रामीणों के साथ, मुखबिर ने उसकी बेटी की जोरदार तलाशी ली, लेकिन उसका (पीड़ित) पता नहीं चल सका।जब मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) को ताला खोलने के लिए कहा गया, तो उसने बताया कि चाबी उसके पास नहीं है।इसके बाद, उसने फुचन पांडे (अपीलार्थी मुन्ना पांडे के भाई) को फोन किया, जो संबंधित समय पर अपने ससुराल में रह रहा था।01-06-2015 पर, नवल किशोर ओझा @फुचन पांडे लगभग 12 बजेः00 दोपहर में उसके घर आया और उसके कमरे का ताला खोला।उक्त कमरे में दिलीप तिवारी के बेटे प्रीतम तिवारी, गांव शोभापुर, पी. एस. राजमहल, जिला-साहेबगंज के निवासी ने खुद को छिपा लिया था।कमरे का ताला बाहर से खोला गया था।जब मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के कमरे का ताला खोला गया तो मुखबिर की बेटी का शव बिस्तर के नीचे मिला।मुखबिर ने दावा किया कि प्रीतम तिवारी और मुन्ना पांडे (अपीलकर्ता) दोनों ने उसकी 11 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और शव को उसके कमरे में छिपा दिया गया था।फरदबेयान को मुखबिर को पढ़ा दिया गया और इसे सही करने के बाद, उसने गाँव जमुनिया के मुखबिर की बहन, पी. एस. परबत्ता, नौगाचिया के बेटे बबलू साओ (पी. डब्ल्यू. 1) की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए।"

4. पीड़ित पीडब्लू 2-किरण देवी की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत (फरदबेयान) के आधार पर, पुलिस ने अपीलार्थी और सह-अभियुक्त प्रीतम तिवारी (अपीलार्थी के बड़े भाई नवल किशोर ओझा उर्फ फुचान पांडे के बहनोई) के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (डी), धारा 34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसी दिन यानी दोपहर 3 बजे सबौर पुलिस स्टेशन में मामला संख्या 106 के रूप में एक औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज की।

5. जाँच के समापन पर, इसमें अपीलार्थी और ऊपर नामित सह-अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।चूँकि अपराध विशेष रूप से एक सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के प्रावधानों के तहत मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया और समर्पण करने पर, इसे पहले अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, भागलपुर के न्यायालय में 2015 के सत्र परीक्षण संख्या 581 के रूप में दर्ज किया गया।

6. निचली अदालत ने अपीलार्थी और सह-अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी), आई. पी. सी. की धारा 34,120 बी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आई. डी. 1 के आदेश के माध्यम से आरोप तय किया।

7. आरोप तय करने के बाद, सह-आरोपी प्रीतम तिवारी ने नाबालिग होने की दलील दी।ऐसी परिस्थितियों में, उनके मामले को निचली अदालत द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के अनुसार अलग कर दिया गया था और किशोर न्याय बोर्ड, भागलपुर को भेज दिया गया था।ट्रायल कोर्ट ने इसमें केवल अपीलार्थी दोषी के खिलाफ कार्यवाही की।

8. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(क) पीडब्लू 1 बबलू सॉ मृतक का चचेरा भाई है और प्रथम सूचना देने वाले की बहन का बेटा है, जिसके स्थान पर सूचना देने वाला 31.05.2015 पर गया था।इस गवाह ने फरदबेयान पर अपने हस्ताक्षर को साबित किया, जिसे एक्सट के रूप में चिह्नित

किया गया था। 1 और उन्होंने मामले की किरण देवी/पीडब्लू 2 (मुखबिर) के हस्ताक्षर को भी साबित किया, जिसे अतिरिक्त के रूप में चिह्नित किया गया था। 1/1।

(ख) पीडब्लू 2 किरण देवी सूचना देने वाली और मृतक की माँ है।(ग) पीडब्लू 3 प्रिया कुमारी मुखबिर की बड़ी बेटी है और मृतक की बड़ी बहन भी है।

(घ) पीडब्लू 4 डॉ. संदीप लाल, जो संबंधित समय में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भागलपुर में तैनात थे, ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया।

(ई) पीडब्लू 5 रीता कुमारी जाँच अधिकारी हैं और उन्होंने मुखबिर का फरदबेयान रिकॉर्ड किया।

(च) पीडब्लू 6 विजय प्रसाद साह एक सह-ग्रामीण हैं और उन्होंने अपदस्थ किया कि उनकी उपस्थिति में, अपीलार्थी के कमरे से शव बरामद किया गया था।

9. मौखिक साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के समापन पर, अपीलार्थी दोषी का आगे का बयान निचली अदालत द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था। अपीलार्थी दोषी ने निम्नानुसार कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“मैं निर्दोष हूँ।मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है।मैं उस घर में नहीं रह रहा था जहाँ से शव बरामद किया गया था।मैं माली तोला में किराए के मकान में रह रहा था।मैंने अपने भाई फुचन पांडे के पक्ष में एक विलेख निष्पादित किया जो थथेरी तोला में स्थित एक पैतृक घर से संबंधित था और मेरा भाई फुचन पांडे उस घर में रह रहा था जहाँ से शव बरामद किया गया था।"

10. अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने पर, विचारण न्यायालय ने एक आदेश दर्ज किया कि इसमें अपीलार्थी उस अपराध के लिए दोषी था जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था।ट्रायल कोर्ट ने मामले को "दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम" की श्रेणी में आने वाले मामले के रूप में माना और अपीलार्थी को मौत की सजा सुनाई।

11. अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और मृत्युदंड से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में गया।उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी दोषी के नेतृत्व में दायर अपील को खारिज कर दिया और 2017 के मृत्यु संदर्भ संख्या 4 में निचली अदालत द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा को स्वीकार कर लिया।

12. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी दोषी वर्तमान अपीलों के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

अपील की प्रस्तुतियाँ

13. अपीलार्थी दोषी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. आदित्य सोंधी ने निम्नलिखित दलीलें दींः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“1. विशुद्ध रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला

1.1 अपीलार्थी, मुन्ना पांडे के खिलाफ मामला केवल अंतिम बार देखे गए साक्ष्य और अपीलार्थी के आचरण पर आधारित है और इसलिए पूरी तरह से परिस्थितिजन्य प्रकृति का है।यह इस माननीय न्यायालय द्वारा तय किया गया एक सुस्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में अभियुक्त के खिलाफ परिस्थितियां निर्णायक होनी चाहिए।

और सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य आरोपी द्वारा किया गया होगा।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **53** ए के तहत चिकित्सा जांच करने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है।

2.1 बलात्कार के मामलों में सीआरपीसी की धारा 53 ए के तहत आरोपी की चिकित्सा जांच आवश्यक है।भले ही अपीलार्थी को गिरफ्तारी के दौरान लगी चोटों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी ऐसी कोई चिकित्सा जांच नहीं की गई थी, जहां डीएनए जांच के उद्देश्य से उनके नमूने एकत्र किए गए थे।

2.2 बलात्कार के मामलों में जहां पीड़ित की मृत्यु हो गई है और केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने की कोशिश की जाती है, चिकित्सा साक्ष्य बहुत महत्व रखता है।अपीलार्थी की चिकित्सीय जाँच कराने में अभियोजन पक्ष की विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है।(छोटकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1313 पैरा 81,82)

2.3 यदि कोई डी. एन. ए. जांच नहीं की जाती है और यदि अभियोजन पक्ष द्वारा डी. एन. ए. जांच नहीं करने के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल परिणाम पड़ेंगे।इसके अलावा, यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त की जांच से अपराध करने के बारे में सबूत नहीं मिलेगा, तो यह काफी संभावना नहीं है कि बलात्कार करने के लिए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया जाएगा।(राजेंद्र प्रह्लादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 12 एस. सी. सी. 495 पैरा 49-57; प्रकाश निषाद @केवट बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 666 पैरा 57,58.59)

3. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ दंडात्मक साक्ष्य को अभिलेख पर नहीं रखा

3.1 अपीलार्थी के अंडरवियर को पुलिस ने 11 बजे 01.06.2023 पर जब्त कर लिया था:45 अपराह्न [पूर्व 6 (जब्त ज्ञापन)], और मृतक के अंडरवियर को 11 बजे 01.06.2015 पर जब्त किया गया था:00 अपराह्न [पूर्व 6/1 (जब्त ज्ञापन)]।हालांकि, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि क्या उन्हें जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था।

3.2 दिनांक 29.06.2015 के आदेश के अनुसार, पीएस सबौर के आधिकारिक प्रभारी की ओर से एक पत्र एलडी ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें वस्तुओं को जांच के लिए एफएसएल पटना भेजने की अनुमति मांगी गई थी।हालाँकि पी. डब्ल्यू. 5, आई. ओ. रीता कुमारी ने 24.10.2016 पर निचली अदालत के समक्ष अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उन्होंने अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के निर्देशों का पालन किया और उन्हें कोई एफ. एस. एल. नहीं मिला।

रिपोर्ट करें।[पीडब्लू5 पैरा 8]

3.3 आगे पोस्टमॉर्टम के समय एकत्र किए गए मृतक के योनि के स्वाब को पीडब्लू 4, डॉ. संदीप लाल द्वारा पैथोलॉजी लैब में भेजा गया।

जाँच।[Ex 2 (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट)।हालांकि, पैथोलॉजिकल

रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि 'शुक्राणु नहीं मिला' अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के समय सबूत के रूप में पेश नहीं किया गया था।

4. अपीलार्थी के खिलाफ अंतिम बार देखे गए साक्ष्य निर्णायक रूप से साबित नहीं हुए

4.1 सभी गवाहों ने अपने 161 बयानों में कहा कि पीड़ित को आखिरी बार प्रीतम तिवारी के साथ देखा गया था।हालाँकि, पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू3 ने अपनी अदालती गवाही में, जो कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रीतम तिवारी को किशोर घोषित किए जाने के 3 महीने बाद दर्ज की गई थी, अपने बयान में सुधार किया और कहा कि यह मुन्ना पांडे था न कि प्रीतम तिवारी।हालाँकि, स्वतंत्र गवाह विजय साह (पीडब्लू 6) द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी।इच्छुक गवाहों की ओर से उक्त सुधार इस तथ्य से प्रेरित हो सकता है कि प्रीतम तिवारी (जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया था) को अब किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत केवल एक उदार सजा दी जाने वाली थी और इसलिए अकेले अपीलार्थी ही विषय मामले में आरोपी बने रहे।

4.2 पीडब्लू3 की अदालती गवाही और उसके 161 बयान में भौतिक विरोधाभास हैं।अपने 161 के बयान में वह कहती है कि प्रीतम तिवारी 09 बजे उसके घर आई थी:00 सुबह और पीड़ित को अपने साथ टीवी देखने ले गया और 2 घंटे बाद उसने प्रीतम तिवारी को बरामदे की ग्रिल को बंद करते देखा।जबकि अपनी अदालती गवाही में, वह कहती है कि मुन्ना पांडे को आखिरी

बार पीड़िता के साथ देखा गया था।पी. डब्ल्यू. 3 को अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान बचाव पक्ष के वकील द्वारा इस विशेष विरोधाभास का सामना करना पड़ा था, लेकिन पी. डब्ल्यू. 3 उक्त विरोधाभास का कोई कारण प्रदान नहीं करता है।

4.3 पीडब्लू2 ने अपने फ़र्दबेयान [पूर्व 1] में, जिसे पीड़ित के शरीर के बरामद होने के ठीक बाद दर्ज किया गया था, अंतिम बार देखे गए साक्ष्य के संदर्भ में अपीलार्थी के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अदालत में उसकी गवाही में सुधार करते हुए कहा है कि अपीलार्थी को आखिरी बार पीड़ित के साथ देखा गया था।पीडब्लू2 को अपनी प्रतिपरीक्षा में इस सुधार का सामना करना पड़ा, जहाँ उसने केवल इतना कहा कि उसने बताया था कि मुन्ना पांडे ने अपनी बेटी पीडब्लू3 से बात की थी और उसने अपने फरदबेयान में यह नहीं कहा था कि पीडब्लू3 ने मुन्ना पांडे को दरवाजा बंद करते हुए देखा था।इस माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विशेष रूप से जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में, जहां बचाव पक्ष के वकील द्वारा अपर्याप्त प्रतिपरीक्षा होती है, निचली अदालतें मूक दर्शक नहीं हो सकती हैं और उनके पास साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 के तहत प्रासंगिक तथ्यों की खोज करने की शक्ति और कर्तव्य है जब गवाहों से ठीक से प्रतिपरीक्षा नहीं की जाती है। (राहुल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (2023) 1 एस. सी. सी. 83 पैरा 42-45)

4.4 अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 31.05.2015 पर 09 बजेः00 जब अपीलकर्ता पीड़ित को लेने के लिए पीडब्लू 3 के घर आया, तो निम्नलिखित व्यक्ति घर में थे-पीड़ित, पीडब्लू 3 और खुशबू देवी (उसकी चाची)।हालाँकि चाची खुशबू देवी से आखिरी बार देखे गए गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए केवल पीडब्लू 3 (एक नाबालिग) से पूछताछ की गई थी।

4.5 ऐसे मामलों में जहां अंतिम बार देखे गए साक्ष्य के संबंध में बाल गवाह की गवाही असंगत है और जब अभियोजन पक्ष द्वारा भौतिक गवाहों से पूछताछ नहीं की जाती है, तो अदालत ने अंतिम बार देखे गए साक्ष्य को सही माना है।(दिगंबर वैष्णव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 4 एससीसी 522 पैरा 40-43)

5. संबंधित समय पर अभियुक्त का आचरण

5.1 नवल किशोर ओझा उर्फ फुचन पांडे और मुन्ना पांडे के बीच अक्सर झगड़े होते थे और इसलिए वे अलग रह रहे हैं।मुन्ना पांडे माली तोला में एक अलग घर में अलग रह रहा था।फुचन पांडे ने अपने घर की चाबी प्रीतम तिवारी को सौंप दी और प्रीतम तिवारी पिछले 2-3 महीनों से फुचन पांडे के घर में रह रहा था।इसके अलावा, मुन्ना पांडे को हर बार ग्रामीणों द्वारा कहीं और से बुलाया जाता था, जो दर्शाता है कि वह उक्त घर में नहीं रहता था।

5.2 स्पॉट मैप और स्पॉट मजार के अनुसार, इमारत में एक बाहरी लोहे की ग्रिल का दरवाजा, एक बरामदा, उत्तर में 1 कमरा और दक्षिण में 1 कमरा है।उत्तर में कमरा फुचन पांडे का है और दक्षिण में कमरा मुन्ना पांडे का है।प्रीतम फूचन पांडे के कमरे के अंदर पाया गया और पीड़ित मुन्ना पांडे के कमरे में पाया गया।मुन्ना पांडे के कमरे में भी लोहे की ग्रिल के बिना 2 खिड़कियां थीं, लेकिन केवल एक बाहरी लकड़ी का पैनल था जो खुला था।एक खिड़की बरामदे की ओर खुली और दूसरी खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुली।टीवी फुचन पांडे के कमरे में था जहाँ प्रीतम निश्चित रूप से रह रहा था।

5.3 बाहरी लोहे की ग्रिल का ताला ग्रामीणों ने तोड़ दिया।जिस कमरे में प्रीतम तिवारी मौजूद थे, उस कमरे में अंदर से ताला लगा हुआ था।मुन्ना पांडे के कमरे का दरवाजा फुचन पांडे द्वारा 01.06.2015 [Ex1] पर लाई गई चाबियों से खोला गया था।

5.4 अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मुन्ना पांडे से चाबी छीनने के बाद ग्रामीणों ने मुन्ना पांडे के कमरे का दरवाजा खोला, हालांकि उसने दावा किया कि पिछले दिन उसके पास घर की चाबी नहीं थी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, इससे उसके आचरण के बारे में गंभीर संदेह पैदा हुए।यह ध्यान रखना उचित है कि इस संदिग्ध आचरण की स्वतंत्र गवाह पीडब्लू6 द्वारा पुष्टि नहीं की गई है।इसके अलावा, मुन्ना पांडे से कथित रूप से चाबी छीनने वाले ग्रामीण मनोज, अनिल और मुर्राई से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई।यह ध्यान देने योग्य है कि मुन्ना पांडे रात भर या अगले दिन जब पीड़ित का शव बरामद हुआ तो वह गांव से नहीं निकला था।इसके अलावा यह विशेष परिस्थिति कि अपीलार्थी ने ग्रामीणों को चाबियाँ देने से इनकार कर दिया और उन्हें डकैती के मामले की धमकी दी, उसके 313 बयान के दौरान उसे नहीं दी गई।इस माननीय न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त के 313 परीक्षण में जिन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।(शरद बर्डीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस. सी. सी. 116 पैरा 145)

6. प्रीतम तिवारी द्वारा मुन्ना पांडे को फंसाने के कथित इकबालिया बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

6.1 अभियोजन पक्ष के अनुसार, गाँव वालों द्वारा प्रीतम तिवारी को फुचन पांडे के घर में पाए जाने के तुरंत बाद, उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और कहा कि उसने मुन्ना पांडे के साथ मिलकर यह अपराध किया था।

मृतक के खिलाफ।हालाँकि, उक्त स्वीकारोक्ति पुलिस अधिकारियों द्वारा पीटे जाने के बाद की गई थी और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में की गई थी।साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत बार के कारण, उक्त स्वीकारोक्ति पर अदालतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा इस कथित स्वीकारोक्ति की पुष्टि स्वतंत्र गवाह विजय साह (पीडब्लू 6) की गवाही से नहीं होती है।प्रीतम तिवारी को भी इस संबंध में गवाह के रूप में पदच्युत नहीं किया गया था।

7. 313 अपीलार्थी की जाँच उचित तरीके से नहीं की गई थी

7.1 अपीलार्थी के 313 परीक्षण में कई महत्वपूर्ण परिस्थितियों को नहीं रखा गया था, हालांकि अपीलार्थी को अपराध के लिए दोषी ठहराने के उद्देश्य से उन्हें दोषपूर्ण माना गया था।वे इस प्रकार हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -• पी. डब्ल्यू. 3 द्वारा अपीलार्थी को अपने कमरे के ग्रिल और दरवाजे को बंद करते हुए देखने की परिस्थिति

• परिस्थिति कि अपीलार्थी ने पीडब्लू3 को गलत जानकारी दी कि पीड़ित टीवी देखने के बाद पहले ही जा चुका था

• अभियुक्त द्वारा दरवाजा खोलने से इनकार करने की परिस्थिति क्योंकि उसके पास चाबी नहीं थी

• अपीलार्थी द्वारा हमला किए जाने के बाद ग्रामीणों को चाबियाँ देने की परिस्थिति

• सह-अभियुक्त प्रीतम तिवारी द्वारा अपीलार्थी को फंसाने वाले कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति की परिस्थिति

7.2 इस माननीय न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी के सामने जो परिस्थितियाँ नहीं रखी गई हैं, उन पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है

8. निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले में खामियां

8.1 निचली अदालत अपने फैसले में सबूतों पर केवल संक्षिप्त चर्चा करती है और गलती से दर्ज करती है कि प्रीतम तिवारी और मुन्ना पांडे घर के अंदर पाए गए थे।

8.2 पटना में उच्च न्यायालय**,** आक्षेपित निर्णय में **[**पैरा **9** पर**]** यह देखता है कि यह प्रथम दृष्टया संतोषजनक है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराने और उसे मौत की सजा देने दोनों में कोई त्रुटि नहीं की है।इस मामले पर अपनी कथित प्रथम दृष्टया राय में यह भारी है **1021**

इच्छुक गवाहों पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू3 के बयान पर निर्भर करता है, जिनमें से सभी ने अपने बयानों में सुधार किया। उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य की अनुपस्थिति, धारा 53 ए की आवश्यकताओं का अनुपालन, एफएसएल रिपोर्ट की अनुपस्थिति और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट की भी अवहेलना की है।अतः उक्त निर्णय विकृति के लिए पर्याप्त है और कानून के विपरीत है।

9. शमन

9.1 गुण-दोष के आधार पर उपरोक्त प्रस्तुतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नीचे दिए गए न्यायालयों ने अपीलार्थी को गलत तरीके से मौत की सजा सुनाई है।

9.2 अपीलार्थी ने 2022 के आई. ए. सं. 172211 के माध्यम से इस माननीय न्यायालय के समक्ष परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों के समर्थन के साथ एक शमन रिपोर्ट का नेतृत्व किया है।निम्नलिखित अपीलार्थी की कम करने वाली परिस्थितियाँ हैं:

((i) कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।

((ii) शाहिद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारागार**,** भागलपुर के अधीक्षक द्वारा प्रमाणित संतोषजनक जेल आचरण।

(iii) पारिवारिक प्रभाव-उनकी गिरफ्तारी के बाद से, उनकी पत्नी संगीता और उनके 2 बेटों-कृष्णा (घटना के समय 18 वर्ष) और बलराम (घटना के समय 12 वर्ष) सहित उनके परिवार को गाँव से बहिष्कृत कर दिया गया था और वे संगीत के माता-पिता के साथ गाँव पंचकठिया, बिहार में रह रहे हैं।

((iv) पारिवारिक संबंध बने रहें

(v) मजबूत सामुदायिक संबंध-मुन्ना पांडे की पत्नी संगीता 2010 में वार्ड पार्षद के रूप में चुनी गई थीं।मोहम्मद के एफ़ी दाऊद के अनुसार।अपीलकर्ता अख्तर @पैरू मियां (सबौर गाँव के निवासी) ने अपनी पत्नी के साथ समुदाय के लिए सक्रिय रूप से काम किया।उन्हें साधन संपन्न माना जाता था और कई ग्रामीण गाँव में अपनी समस्याओं के साथ उनसे संपर्क करते थे।

((vi) अपीलार्थी की आयु**-**वह वर्तमान में **56** वर्ष का है **(vii)** सुधार की प्रबल संभावना।

(बल दिया गया)

14. ऐसी परिस्थितियों में, ऊपर उल्लिखित, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उसकी अपीलों में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जाए और दोषसिद्धि और मृत्युदंड के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी किया जा सके।

प्रोसेक्शन के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

15. दूसरी ओर, इन अपीलों का राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री समीर अली खान ने जोरदार विरोध किया।उन्होंने प्रस्तुत किया कि निचली अदालतों द्वारा अपीलार्थी को आरोपित अपराध का दोषी ठहराने और मामले को "दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम" की श्रेणी में आने वाला मानने में कानून की किसी भी त्रुटि की बात नहीं की जा सकती है।

16. विद्वान वकील ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि यह अपीलकर्ता ही था जो आईडी1 की सुबह 9 बजे पीड़ित के घर गया था और पीड़ित को टीवी देखने के लिए अपने घर आने का लालच दिया था। यह तर्क दिया गया कि सभी गवाहों ने गवाही दी है कि पीड़ित सुबह 31.05.2015 पर टीवी देखने के लिए अपीलार्थी के घर गई थी और उसके बाद वह लापता हो गई थी। उन्होंने कहा कि पीड़ित की बहन प्रिया कुमारी (पीडब्लू 3) ने तुरंत अपनी मां किरण देवी (पीडब्लू 2) को सूचित किया जो प्रासंगिक समय पर एक अलग गाँव में अपनी बहन के घर पर थी।जैसे ही पीड़िता की मां को पता चला कि उसकी बेटी लापता है, वह तुरंत अपने घर वापस चली गई और अपनी नाबालिग बेटी के ठिकाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी।यह तर्क दिया गया कि कहा जा सकता है कि पीड़ित को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था।यह भी तर्क दिया गया कि जब घर खोला गया था, तो पीड़ित का शव एक खाट के नीचे बरामद किया गया था और जिस कमरे से शव बरामद किया गया था, वह अपीलार्थी का था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह अपीलार्थी को समझाना है कि पीड़ित का शव उसके घर के कमरे से कैसे बरामद किया गया, जिस पर उसका पूरा नियंत्रण था।यह भी तर्क दिया गया कि पीडब्लू 3 प्रिया कुमारी ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने अपीलार्थी को अपने कमरे का दरवाजा बंद करते देखा था।यह इस तथ्य का संकेत है कि कमरे की चाबियाँ अपीलार्थी के पास थीं।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि स्थापित तथ्य केवल अपीलार्थी दोषी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप हैं और एक निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति के हैं।उन्होंने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूरी है कि यह 1023 नहीं छोड़ती है।

अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार।

17. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं होने के कारण, उन्हें खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

18. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की है?

19. यह मामला एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का एक बहुत ही वीभत्स मामला है।अभियोजन पक्ष का मामला है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पीड़ित टीवी देखने के लिए अपीलार्थी के घर गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह अपीलकर्ता ही था जो पीड़िता के घर आया और उसे टीवी देखने के लिए उसके घर आने के लिए राजी किया। पीड़ित की बड़ी बहन, पीडब्लू 3 प्रिया कुमारी घर पर थी जब उसकी छोटी बहन टीवी देखने के लिए अपीलार्थी के घर गई थी। जब छोटी बहन अपने घर वापस नहीं आई, तो प्रिया कुमारी ने उसकी तलाश शुरू कर दी और जब उसे अपनी छोटी बहन के ठिकाने का पता नहीं चला, तो उसने तुरंत अपनी मां किरण देवी (पहली सूचना देने वाली) को सूचित किया।संबंधित समय में, किरण देवी जमुनिया परबत्ता में अपनी बड़ी बहन शकीला देवी के घर पर थीं।पीडब्लू1 बबलू सॉ शकीला देवी के पुत्र हैं।पीडब्लू 2 किरण देवी पीडब्लू 1 बबलू सॉ की मौसी हैं। अभियोजन पक्ष का मामला है कि जब किरण देवी अपनी बड़ी बहन शकीला देवी के घर पर थी, तो प्रिया कुमारी ने उसे टेलीफोन पर बताया कि पीड़िता सुबह अपीलार्थी के घर टीवी देखने गई थी और उसके बाद वह लापता हो गई थी।यह पीडब्लू 1 बबलू सॉ था जो किरण देवी को अपनी मोटरसाइकिल पर उनके गाँव यानी उनके घर वापस ले आया।

20. अब हम उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित फैसले में दर्ज किए गए तथ्यों पर गौर करेंगे।दूसरे शब्दों में कहें तो, उच्च न्यायालय द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था और अपीलार्थी को कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए तर्क की रेखा इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“9. ... शुरुआत में, प्रथम हाथ की जानकारी की जांच करना आवश्यक होगा, जो सूचना देने वाली पी. डब्ल्यू. 3 अर्थात् प्रिया कुमारी की बड़ी बेटी के मुंह से आई है।वह मुख्य थी

गवाह, जिसने उस अपीलार्थी को देखा था, उसने पीड़ित को टी. वी. धारावाहिक देखने के बहाने अपने साथ जाने के लिए राजी किया और लुभाया।

10. ... मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) ने पीड़ित को उठाया, उस समय लगभग 9 बज रहे थेः00 एएम (सुबह)।खाना तैयार करने के बाद, वह पीड़िता को मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के घर बुलाने गई, फिर उसने देखा कि मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) उसके दरवाजे पर ताला लगा रहा था।उसने देखा कि मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) अपने कमरे में ताला लगाने के बाद बाहर आ रहा था।जब वह गेट के पास पहुंची, तब तक मुन्ना पांडे (अपीलकर्ता) भी गेट पर ताला लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तब उसने मुन्ना पांडे से पूछा कि पीड़ित कहाँ है, मुन्ना पांडे (अपीलकर्ता) ने जवाब दिया कि वह टी. वी. को देखने के बाद पहले ही जा चुकी थी।पी. डब्ल्यू. 3 इसके बाद उसके घर वापस आई और पास में तलाशी लेने की कोशिश की।जब उसने पीड़िता की पहचान नहीं की तो उसने अपनी मां (पी. डब्ल्यू. 2, किरण देवी) को फोन किया और उसे सूचित किया।उसी तारीख को उसकी माँ अपने (प्रिया) चचेरे भाई बबलू (पी. डब्ल्यू. 1) के साथ वापस आई।फिर से, इस गवाह ने अपनी माँ को सब कुछ बताया।इसके बाद, वह, उसकी माँ, चाची और चचेरे भाई बबलू, सभी ने संयुक्त रूप से खोज शुरू की, लेकिन पीड़ित का पता नहीं चला, फिर वे मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के घर गए, जहाँ यह देखा गया कि मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के कमरे में ताला लगा हुआ था।बाहर का गेट भी बंद था।इसके बाद, उसने अन्य ग्रामीणों से पूछताछ की, जिस पर ग्रामीणों ने मुन्ना पांडे को बुलाया, फिर वह आया।अपीलार्थी से ग्रामीणों और उसकी माँ (पी. डब्ल्यू. 2) ने भी पीड़ित के बारे में पूछताछ की।अपीलार्थी ने कहा कि उसके पास कमरे की चाबी नहीं थी।इस तथ्य को देखने के बाद, ग्रामीणों ने कहा कि अगर उसके पास चाबी नहीं थी, तो वे ताला तोड़ देंगे।जिस पर, अपीलार्थी ने उन्हें ताला तोड़ने पर डकैती के मामले में फंसाने की धमकी दी।मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) ने यह भी कहा कि प्रीतम (सह-अभियुक्त) का भी पता नहीं चल रहा था और उसने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह पीड़ित के साथ कहीं गया था।मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के इस तरह के बयान के बल पर, उन्होंने प्रीतम की भी तलाश शुरू कर दी, हालांकि उनका पता नहीं चल सका और उसके बाद, वे अपने घर लौट आए और फिर से वे मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के घर गए, जहाँ उसने देखा कि फुचन पांडे के घर के अंदर से कुछ रोशनी आ रही थी।इसके बाद, गाँव वालों ने कुछ संदेह व्यक्त किया, जैसे कि कमरे में कोई है।मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) को फिर से ताला तोड़ने के लिए कहा गया, फिर उन्होंने कहा कि कुंजी 1025

फुचान पांडे के साथ लेटा हुआ था।इसके बाद ग्रामीणों ने फुचान को फोन किया, उसी समय वह अपने ससुराल में था।फुचान ने टेलीफोन पर बताया कि वह सुबह आएगा।8 से:00 सुबह, फुचान नहीं आया, पी. डब्ल्यू. 3 अपनी माँ के साथ सबौर पुलिस स्टेशन गई, हालाँकि इस बीच, फुचान अपने घर पहुँच गया।ग्रामीणों ने बल प्रयोग करके मुन्ना को भी धक्का दिया और उसे उक्त स्थान पर ले गए।इसके बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई।बाहरी दरवाजे का ताला तोड़ दिया गया था।इसके बाद, कमरे की चाबी मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) द्वारा प्रदान की गई।फुचान के कमरे से प्रीतम तिवारी बाहर आया।पुलिस और ग्रामीणों की उपस्थिति में प्रीतम से पूछा गया कि पीड़ित कहाँ है, फिर उसने समझाया कि पीड़ित मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के कमरे में है।प्रीतम ने यह भी कहा कि उसने और मुन्ना पांडे दोनों ने संयुक्त रूप से पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के बिस्तर के नीचे पीड़ित का शव मिला।उसका शरीर निर्वस्त्र था।उसका मूत्र भाग सूज गया था और खून निकल रहा था।उसने अपना कचरा (पॉटी) भी तितर-बितर कर दिया था और वह भी फूल गया था।पुलिस शव को अपने साथ ले गई।उसने दोनों अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान करने का दावा किया, जिसमें अपीलार्थी भी शामिल है।पैराग्राफ-2 में प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा कि उनके पिता गुजरात में रह रहे थे।उन्होंने आगे कहा कि फुचन पांडे को नवल किशोर ओझा के नाम से भी जाना जाता है।अपनी जिरह के पैराग्राफ-7 में, उसने दावा किया कि उसने कमरे में टेलीविजन देखा था, जहाँ एक बिस्तर, पंखे सहित अलमारी थी।पैराग्राफ-8 में, उसने आगे कहा कि वह उक्त कमरे में जा रही थी और कहा कि मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) उसका पड़ोसी था।पैराग्राफ-9 में उन्होंने बताया कि पीड़ित की तलाश में वे ब्लॉक, चौक, स्टेशन सबौर आदि सहित कई स्थानों पर गए थे। पैराग्राफ 12 में, उन्होंने कहा कि फुचन पांडे और मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) पूर्ण भाई थे और दोनों भाइयों के पास अपने हिस्से में एक-एक कमरा था।उसने पैराग्राफ 12 में कहा कि मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) वस्तुतः कहीं और रह रहा था और आमतौर पर वह अपने कमरे (घटना स्थल) में जाता था।उसने आगे कहा कि वह मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के किराए के घर के बारे में नहीं जानती थी।फिर से, पैराग्राफ 12 में ही, उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि पहले मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी।यह इंगित करना आवश्यक है कि घटना से पहले अपीलार्थी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, जिससे पता चलता है कि

किसी भी पुरानी दुश्मनी के कारण गलत निहितार्थ का मामला नहीं था।बेशक, उनके पिछले बयान की ओर उनका ध्यान उनकी जिरह के पैराग्राफ 13 में खींचा गया था, लेकिन जब जांच अधिकारी की जांच की जा रही थी, तो कोई विरोधाभास नहीं था और इस तरह, ऐसी तथाकथित छोटी विसंगतियों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।उसने इस सुझाव का खंडन किया कि उसने झूठा सबूत दिया था और अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाया था।पी. डब्ल्यू. 3 के पूरे साक्ष्य की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि हालांकि इस गवाह से विस्तार से जिरह की गई थी, लेकिन उसके साक्ष्य पर कोई संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी नहीं निकाला जा सका।

11. ... मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) को भी ग्रामीणों ने बुलाया था।जब गाँव वालों ने फुचान को ताला खोलने के लिए कहा, तो फुचान ने जवाब दिया कि उसके पास चाबी नहीं है।इसके बाद ग्रामीणों ने मुन्ना पांडे पर हमला करना शुरू कर दिया और उसे ताला तोड़ने के लिए कहा।जब ग्रामीणों ने एक ताला तोड़ा, तो मुन्ना पांडे (अपीलकर्ता) ने चाबी निकाल ली और उस चाबी से फुचान के दरवाजे का ताला खोल दिया गया, लेकिन कमरा अंदर से बंद था।जब दरवाजा खटखटाया गया तो प्रीतम ने उसे खोल दिया और उसने खुद को छिपा लिया।गाँव के सभी लोग घर में घुस गए।पुलिस भी आ गई।प्रीतम को पकड़ लिया गया।जब प्रीतम पर हमला किया जा रहा था, तब पुलिस वहां पहुंच गई थी।गाँव वालों ने मुन्ना के कमरे का ताला भी खोल दिया।मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के कमरे से पीड़ित का शव बरामद किया गया।पीड़ित की उम्र 11 साल थी और शव को बिस्तर के नीचे रखा गया था और पुलिस ने बिस्तर के नीचे से शव को बाहर निकाला।सूचना देने वाला रोने लगा।उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी का कपड़ा निचले हिस्से से हटा दिया गया था।उसने देखा कि उसकी बेटी का मूत्र भाग टूट गया था और उसने वहाँ पॉटी भी देखी। उसने कहा कि गुदा भी फट गया था।चेहरा सूज गया था और गाल पर भी चोट के निशान थे।इसके बाद ग्रामीणों ने मुन्ना, प्रीतम और फुचान पर हमला करना शुरू कर दिया।प्रीतम ने पुलिस की उपस्थिति में कहा कि उसने और मुन्ना पांडे दोनों ने संयुक्त रूप से अपराध किया था।इस गवाह ने कहा कि उसका फरदबेयान पुलिस द्वारा घटना स्थल पर ही दर्ज किया गया था और उसने फरदबेयान पर अपने हस्ताक्षर के साथ-साथ बबलू (पी. डब्ल्यू. 1) के हस्ताक्षर की पहचान की थी।हस्ताक्षर की पहचान एक्सट के रूप में की गई थी। 1/1।उसने प्रीतम और मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) की पहचान करने का दावा किया।जिरह के समय, ट्रायल जज ने देखा कि यह गवाह बहुत घबराई हुई थी और वह बार-बार रो रही थी और यह संख्या 1027 थी

कारण कि उस तारीख यानी 21.06.2016 पर प्रतिपरीक्षा स्थगित कर दी गई थी।यह प्रतिबिंब पीड़ित की माँ द्वारा दी गई पीड़ा के बारे में बताता है।अपनी जिरह के पैराग्राफ 8 में, उसने कहा कि प्रिया (पी. डब्ल्यू. 3) ने टेलीफोन पर सूचित किया था कि पीड़ित लापता थी।उसने अपनी जिरह के पैराग्राफ-8 में आगे कहा कि सूचना देने वाले के परिवार के सदस्य मुन्ना पांडे के साथ मिलने आए थे और वह सूचना देने वाले के घर भी जा रहा था।अपनी जिरह के पैराग्राफ-10 में, उसने कहा कि वह अपीलार्थी की आपराधिक प्रकृति के बारे में कुछ नहीं जानती थी।उसने कहा कि अपीलार्थी उसका पड़ोसी था और यही उनके बातचीत का कारण था।अपनी जिरह के पैराग्राफ-11 में उन्होंने कहा कि जिस कमरे में प्रीतम मौजूद थे, वह खोला गया था।मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के कमरे का ताला खोल दिया गया।मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) और फुचन पांडे अलग-अलग रह रहे थे।एक कमरा फुचान का था और एक कमरा मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) का था।उसने पैराग्राफ-12 में स्पष्ट किया कि घटना से कुछ दिन पहले ही फुचान शोभाबुर गांव में स्थित अपने ससुराल जा चुका था।अपनी जिरह के पैराग्राफ-17 में, उसने दोहराया कि उसकी पीड़ित बेटी का शव मुन्ना पांडे के कमरे में मिला था, जबकि प्रीतम तिवारी ने खुद को फुचान के कमरे में छिपा लिया था।अपनी जिरह के पैराग्राफ 19 और 20 में, पी. डब्ल्यू. 2 ने इस सुझाव का खंडन किया कि दो कमरों का ताला फुचान पांडे द्वारा खोला गया था और इस सुझाव का खंडन किया कि मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के कमरे का ताला भी फुचान पांडे द्वारा खोला गया था।अपनी जिरह के पैराग्राफ-23 में, उसने कहा कि वह फरदबेयान रिकॉर्ड करने की सही तारीख नहीं कह सकती है, हालांकि उसने कहा कि वह उस दिन कह सकती है जिस दिन इसे रिकॉर्ड किया गया था।उन्होंने कहा कि रीता मैडम यानी पी. डब्ल्यू. 5 ने फरदबेयान रिकॉर्ड किया था और इसे उन्हें पढ़ा दिया गया था। उसे ठीक से याद नहीं था कि वह समय क्या था।अपनी जिरह के पैराग्राफ 26 और 27 में, उसने कहा कि फुचान के आने के बाद, जब उसने चाबी रखने से इनकार कर दिया, तो ग्रामीणों ने मुन्ना पांडे (अपीलकर्ता) पर हमला करना शुरू कर दिया।उसने कहा कि प्रीतम को विजय (पीडब्लू 6) बबलू (पीडब्लू 1) और अन्य ग्रामीणों ने पकड़ लिया था और उन्होंने प्रीतम को थप्पड़ भी मारा था।पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ-28 में उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का शव मुन्ना पांडे (अपीलार्थी) के घर में मिला था।उसकी जाँच करने पर

जिरह सहित संपूर्ण साक्ष्य, यह स्पष्ट है कि घटना से संबंधित प्रत्येक तथ्य को जिरह में दोहराया गया था, लेकिन उसके साक्ष्य पर कुछ भी संदेह नहीं किया जा सकता था।

×××

×××

×××

16. पूरे साक्ष्य की जांच करने पर, यह स्थापित किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है।विद्वत विचारण न्यायाधीश ने दिनांक आई. डी. 2 के अपने निर्णय द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराने के बाद सजा की तारीख को स्थगित कर दिया और उचित समय के बाद आई. डी. 1 पर विद्वत विचारण न्यायाधीश, दोनों पक्षों को सुनने और उग्र और कम करने वाली परिस्थितियों को संतुलित करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मौत की सजा देने के लिए एक अंतिम मामला था और उसके बाद, मौत की सजा सुनाई गई और इसे आई. डी. 3 की धारा 366 के तहत इस न्यायालय को भेजा गया।17. पी. डब्ल्यू. 3 का साक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि घटना की तारीख को सुबह यह अपीलार्थी सूचना देने वाले के घर पहुंचा था, जबकि उसी समय पी. डब्ल्यू. 3 भोजन तैयार कर रहा था।उसकी उपस्थिति में, इस अपीलार्थी ने कहा, बल्कि पीड़ित को अपने घर के अंदर टी. वी. कार्यक्रम देखने के लिए अपने साथ जाने का लालच दिया।पहली बार में, पीड़ित की बड़ी बहन पी. डब्ल्यू. 3 ने कहा कि वह भोजन करने के बाद ही जा सकती है, लेकिन उसे भी अपीलार्थी ने रोक दिया और उसने (अपीलार्थी) जोर देकर कहा और उसके बाद ही, पीड़ित, जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी, अपने घर में टी. वी. कार्यक्रम देखने की आड़ में अपीलार्थी के साथ गई थी।पीडब्लू. 2 के मुखबिर/पीड़ित की माँ के साक्ष्य में, यह तथ्य सामने आया है कि अपीलार्थी मुखबिर का पड़ोसी था और वे मुलाकाती अवधि पर थे।इसका अर्थ यह है कि उस समय, जब अपीलार्थी ने पीड़ित को बुलाया था, बड़ी बहन के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसकी लगभग 11 वर्ष की छोटी बहन के साथ अपीलार्थी द्वारा बलात्कार किया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से घटना की तारीख को न तो जवान थी और न ही बहुत बूढ़ी थी।दोषसिद्धि और सजा के निर्णय से यह प्रतीत होता है कि उसकी (अपीलार्थी) आयु 50 वर्ष आंकी गई थी।इसका मतलब यह है कि कल्पना से परे, बड़ी बहन को कोई आशंका नहीं थी कि उसकी नाबालिग बहन के साथ एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया जा सकता है, जो पड़ोसी था और जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी।यही कारण था कि पीड़ित को अपीलार्थी के साथ जाने की अनुमति दी गई थी।

पीड़ित, जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी, इस तथ्य से भी अनजान थी कि अपीलार्थी के दिमाग में क्या हो रहा था।उसे कमरे में ले जाने के बाद और कुछ घंटों के भीतर, जब पीडब्लू. 3 (पीड़ित की बड़ी बहन) अपीलार्थी के घर गई, तो उसने देखा कि यह अपीलार्थी दरवाजा बंद करने के बाद बाहर आ रहा था।यह अंत नहीं था, पूछताछ पर भी, इस अपीलार्थी ने झूठी घोषणा की कि पीड़ित टी. वी. कार्यक्रम देखने के बाद ही चला गया था।फिर से अपीलार्थी का आपराधिक दिमाग काम कर रहा था और यही कारण था कि भले ही वह पहले ही 11 साल की लड़की के साथ बलात्कार और हत्या कर चुका था और शव को अपने कमरे के अंदर छिपा चुका था, लेकिन उसने पीड़ित की बड़ी बहन (पी. डब्ल्यू. 3) को गलत जानकारी दी।चूँकि पीड़ित का पी. डब्ल्यू. 3 (प्रिया) द्वारा पता नहीं लगाया जा सका, पी. डब्ल्यू. 3 जिसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष थी, और यही कारण था कि वह आगे कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी और उसने तुरंत अपनी माँ (मुखबिर) से संपर्क किया, जो लगभग 22 किलोमीटर दूर गाँव जमुनिया गई थी।सबौर गाँव से दूर।उसने अपनी माँ को पीड़ित के लापता होने के बारे में सूचित किया और उसने अन्य परिस्थितियों के बारे में भी बताया, जो अपीलार्थी पर संदेह करने के लिए पर्याप्त थीं।इसके बाद, जमुनिया से मुखबिर अपनी दिवंगत बहन पी. डब्ल्यू. 1 (बबलू सॉ) के बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर आया और वे सभी फिर से अपीलार्थी के घर गए और इस बार उन्होंने देखा कि घर के साथ-साथ अपीलार्थी का बाहरी गेट भी बंद था और कोई नहीं था, फिर पीड़ित की तलाशी ली गई।इसके बाद, ग्रामीणों ने अपीलार्थी को बुलाया, जिसने खुलासा किया कि उसके पास चाबी नहीं थी और उसने नाटक किया, जैसे कि चाबी उसके भाई फुचान पांडे के पास रह गई थी, जो दूर था और अपने ससुराल में रह रहा था।इस बार फिर इस अपीलार्थी ने गलत जानकारी दी।तलाशी के माध्यम से दिन का समय समाप्त हो गया था और शाम को मुखबिर पक्ष और ग्रामीणों ने अपीलार्थी के घर से कुछ रोशनी आती देखी, फिर संदेह मजबूत हुआ।इसके बाद, ग्रामीणों ने दरवाजा खोलने के लिए अपीलार्थी को फिर से बुलाया।उसके इनकार करने पर, ग्रामीणों ने कहा कि वे दरवाजे का ताला तोड़ देंगे, उस घटना में, इस अपीलकर्ता ने ग्रामीणों को धमकी दी कि अगर ताला तोड़ा गया तो वह उनके खिलाफ डकैती का मामला दर्ज कराएगा।वे सभी बातें अपीलार्थी के आपराधिक दिमाग के बारे में दर्शाती हैं।अगली सुबह जब उसका भाई फुचान आया, जिसे टेलीफोन पर आने के लिए कहा गया, और उसने खुलासा किया कि उसके पास चाबी नहीं है, तो गाँव वाले आने लगे।

अपीलार्थी पर हमला करने के लिए और एक ताला तोड़ा गया और उसके बाद ही, इस अपीलार्थी ने चाबी निकाल ली।बेशक बाद में, कमरा, जिसे अपीलार्थी के कब्जे में बताया गया था, खोला गया और अपीलार्थी के बिस्तर के नीचे, पीड़ित का क्षत-विक्षत हालत में शव पाया गया।जैसा कि सूचना देने वाले/पी. डब्ल्यू. 2, P.W.3/Priya और P.W.1/Babloo द्वारा समझाया गया था, यहाँ पहले ही सब कुछ चर्चा की जा चुकी है।"

(जोर दिया गया) 21.इस प्रकार, पूरे समय, उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि यह अपीलार्थी दोषी था जो 31.05.2015 की सुबह पीड़िता के घर आया और उसे टीवी देखने के लिए उसके घर आने का लालच दिया। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि चूंकि पीड़ित का शव अपीलार्थी के स्वामित्व वाले कमरे से बरामद किया गया था और उसे पीडब्लू 3 प्रिया कुमारी ने अपने घर से जुड़ा दरवाजा बंद करते हुए देखा था, इसलिए यह अपीलार्थी के अलावा और कोई नहीं हो सकता है जिसे अपराध करने वाला कहा जा सकता है।उच्च न्यायालय पूरी तरह से भूल गया कि तस्वीर में प्रीतम तिवारी नाम का एक सह-अभियुक्त भी था।प्रीतम तिवारी के किशोर होने के कारण उन पर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया और तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

एफ**.** एस**.** एल**.** रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गयाः

22. हमने पूरी जांच में कुछ बहुत गंभीर खामियों को देखा और विशेष रूप से, जांच अधिकारी पीडब्लू 5 रीता कुमारी के मौखिक साक्ष्य ने हमें बहुत परेशान किया।जाँच अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि पुलिस स्टेशन, सबौर के प्रभारी अधिकारी की ओर से दिनांकित 29.06.2015 के आदेश के अनुसार एक पत्र को ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मुद्दमल लेखों को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल), पटना को जांच के लिए भेजने की अनुमति मांगी गई थी। हालाँकि, पीडब्लू 5 रीता कुमारी ने निचली अदालत के समक्ष अपनी जिरह में स्वीकार किया कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए, उन्होंने एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।पीडब्लू 5 के ये वरिष्ठ अधिकारी कौन हैं और उन्होंने पीडब्लू 5 को एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त नहीं करने का निर्देश क्यों दिया, यह राज्य के साथ-साथ निचली अदालत दोनों द्वारा जांच का विषय होना चाहिए था।

23. उपरोक्त चूक हिमशैल का सिर्फ एक सिरा है।हम यह कहते हुए दुखी हैं कि यह जांच अधिकारी की ओर से बहुत गंभीर मामला है और वह भी इतने गंभीर मामले में।

1031

मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1032 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

चिकित्सकीय परीक्षा आयोजित करने में विफलता

24. वर्तमान मामले में जांच अधिकारी की ओर से एक और गंभीर बात जो हमारे संज्ञान में आई है, वह है अपीलार्थी को एक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा जांच के अधीन करने में विफलता।जाँच अधिकारी की ओर से इस तरह के गंभीर आरोप के लिए कोई स्पष्टीकरण, बहुत कम कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

25. सी. आर. पी. सी. की धारा 53 (1) सब-इंस्पेक्टर के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी जांच करने का अनुरोध करने के लिए सक्षम बनाती है, जो उन तथ्यों का पता लगाने के लिए उचित रूप से आवश्यक है जो इस तरह के साक्ष्य का समर्थन कर सकते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को इस तरह की प्रकृति का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होते हैं कि उसके व्यक्ति की जांच से अपराध करने के लिए सबूत मिल जाएगा।धारा 53 (1) इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"धारा **53.**चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की जाँच

पुलिस अधिकारी का अनुरोध।— (1) जब किसी व्यक्ति को ऐसी प्रकृति का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और उस पर ऐसी परिस्थितियों में अपराध करने का आरोप लगाया जाता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि उसके व्यक्ति की जांच अपराध करने के संबंध में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो उप-निरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करने वाले एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उसकी सहायता में और उसके निर्देश के तहत सद्भावना से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी जांच करना वैध होगा जो उन तथ्यों का पता लगाने के लिए उचित रूप से आवश्यक है जो ऐसे साक्ष्य को प्रदान कर सकते हैं, और उस उद्देश्य के लिए उचित रूप से आवश्यक बल का उपयोग करने के लिए।"

26. 2005 के अधिनियम 25 द्वारा, मूल स्पष्टीकरण के स्थान पर धारा 53 के तहत एक नया स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया गया था।2005 के अधिनियम 25 द्वारा धारा 53 के तहत इस प्रकार प्रतिस्थापित स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"स्पष्टीकरण-इस धारा में और धारा 53 क और 54 में -

(क) "परीक्षण" में रक्त, रक्त के दाग, वीर्य, यौन संबंध के मामले में स्वाब, थूक और पसीने, बालों के नमूने और डीएनए प्रोफाइलिंग सहित आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग से नाखूनों की कतरनों की जांच और ऐसे अन्य परीक्षण शामिल होंगे जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशेष मामले में आवश्यक समझते हैं।

(बी) "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से एक चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खंड (एच) में अवज्ञा के रूप में कोई चिकित्सा योग्यता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किया गया है।"

27. साथ ही 2005 के अधिनियम 25 की धारा 53 के तहत एक नए स्पष्टीकरण के प्रतिस्थापन के साथ एक नया प्रावधान यानी धारा 53 ए भी जोड़ा गया। धारा 53 ए इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"धारा **53** क। बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच

अभ्यासी।— (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्कार करने या बलात्कार करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होते हैं कि उसके व्यक्ति की जांच से ऐसी गलती होने के बारे में सबूत मिलेंगे, तो यह सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए वैध

होगा और ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में उस स्थान से सोलह किलोमीटर के दायरे में जहां पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर काम करने वाले किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अपराध किया गया है, जो उप-निरीक्षक के पद से कम नहीं है, और उसकी सहायता में और उसके निर्देश के तहत सद्भावना से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी जांच करना और उसका उपयोग करना वैध होगा।

(2) ऐसी परीक्षा का संचालन करने वाला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना किसी देरी के, ऐसे व्यक्ति की जांच करेगा और निम्नलिखित विवरण देते हुए उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, अर्थात् -

((i) अभियुक्त और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा उसे लाया गया था,

((ख) अभियुक्त की आयु,

((ग) अभियुक्त व्यक्ति पर चोट के निशान, यदि कोई हों,

((iv) डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के लिए अभियुक्त व्यक्ति से ली गई सामग्री का विवरण, और

((v) उचित विस्तार से अन्य सामग्री विवरण।

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष पर पहुंचने के सटीक कारण बताए जाएँगे।

1033

मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1034 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

(4) परीक्षा शुरू होने और पूरी होने का सही समय भी रिपोर्ट में नोट किया जाएगा।

(5) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना किसी देरी के, जाँच अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जो इसे उस धारा की उप-धारा (5) के खंड (ए) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के हिस्से के रूप में धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।"

28. छोटकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (2023) 6** एस**.** सी**.** सी**. 742** में इस न्यायालय की तीन**-**न्यायाधीशों की पीठ को सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **53,53**ए और **164** पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिला।इस न्यायालय ने पैरा **80** से **83** में निम्नलिखित टिप्पणी कीः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

“80. यह कहने के बाद कि धारा 53-ए अनिवार्य नहीं है, इस न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा 54 में पाया कि अभियोजन पक्ष की डी. एन. ए. साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता, एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की गारंटी देती है।पैरा 54 इस प्रकार हैः(राजेन्द्र प्रल्हादराव वासनिक मामला [राजेन्द्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 12 एस. सी. सी. 460: (2019) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 420], एस. सी. सी पी.485)

“54. अभियोजन पक्ष द्वारा डी. एन. ए. साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, विशेष रूप से जब देश में डी. एन. ए. प्रोफी लिंग की सुविधा उपलब्ध है।अभियोजन पक्ष को इसका लाभ उठाने की अच्छी सलाह दी जाएगी, विशेष रूप से धारा 53-ए और धारा 164-ए. सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों को देखते हुए। हम यह सुझाव देने की हद तक नहीं जा रहे हैं कि यदि कोई डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग नहीं है, तो अभियोजन पक्ष का मामला साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारा निश्चित रूप से यह विचार है कि जहां डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग नहीं की गई है या इसे निचली अदालत से रोक दिया गया है, तो अभियोजन पक्ष के लिए एक प्रतिकूल परिणाम होगा।"

81. इस स्तर पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 2005 के उसी संशोधन अधिनियम 25 द्वारा, जिसके द्वारा धारा 53-ए डाली गई थी, संहिता में धारा 164-ए भी डाली गई थी।जबकि धारा 53-ए बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सा जांच को सक्षम बनाती है, धारा 164-ए बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा जांच को सक्षम बनाती है।ये दोनों प्रावधान कुछ हद तक समान हैं और इन्हें लगभग एक-दूसरे की दर्पण छवि कहा जा सकता है।लेकिन तीन विशिष्टताएँ हैं।वे इस प्रकार हैं:

81.1 धारा 164-ए में बलात्कार की शिकार महिला की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।वैकल्पिक रूप से, पीड़ित की चिकित्सा जांच से पहले उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए थी।धारा 53-ए ऐसी किसी भी सहमति के बारे में नहीं बताती है।

81.2 धारा 164-ए में चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा महिला की सामान्य मानसिक स्थिति को शामिल करने की आवश्यकता है।यह धारा 53-ए में अनुपस्थित है।

81.3 धारा 164-ए (1) के तहत, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा जांच अनिवार्य है, जब जांच के दौरान "महिला के व्यक्ति की चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा जांच कराने का प्रस्ताव है"।यह इन शब्दों के उपयोग से पता चलता है, "ऐसी परीक्षा आयोजित की जाएगी"।इसके विपरीत, धारा 53-ए (1) केवल एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति की जाँच करना विधिसम्मत बनाती है यदि "यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि उसके व्यक्ति की जाँच इस तरह के अपराध के लिए साक्ष्य प्रदान करेगी।"

82. जिन मामलों में बलात्कार की पीड़िता जीवित है और अदालत में गवाही देने की स्थिति में है, वहां अभियोजन पक्ष के लिए आरोपी की चिकित्सकीय जांच नहीं करके एक मौका लेना संभव हो सकता है।लेकिन ऐसे मामलों में जहां पीड़ित की मृत्यु हो गई है और केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा ही इसे स्थापित करने की कोशिश की जाती है, चिकित्सा साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। अभियुक्त या किसी की ओर से कोई बाधा नहीं होने के बावजूद, इस तरह के साक्ष्य पेश करने में अभियोजन पक्ष की विफलता निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले में एक बड़ा छेद पैदा करेगी और अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर संदेह पैदा करेगी। हम इस सवाल में नहीं जाना चाहते कि धारा 53-ए अनिवार्य है या नहीं।धारा 53-ए अभियोजन पक्ष को आरोप साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।इस मामले में अभियोजन पक्ष की अपीलार्थी की चिकित्सीय जांच कराने में विफलता निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है, विशेष रूप से जब नेत्र साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाया जाता है।

83. पीड़ित द्वारा पहने गए सलवार पर खून/वीर्य के दाग पर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त करने में उनकी विफलता, अभियोजन पक्ष की विफलता को बढ़ाती है।"

1035

मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1036

29. इस प्रकार, एक अभियुक्त की चिकित्सीय जांच उन मामलों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है जहां बलात्कार की पीड़िता की मृत्यु हो गई है और केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा अपराध स्थापित करने की कोशिश की जाती है।

धारा **313** सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** के तहत अगला वक्तव्य

30.....अपीलार्थी दोषी का आगे का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था। जिस तरह से निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थी दोषी का आगे का बयान दर्ज किया, उसे देखकर हम हैरान रह गए। कुल मिलाकर, अपीलार्थी दोषी से चार प्रश्न पूछे गए ताकि वह कथित अपराध में अपनी संलिप्तता की ओर इशारा करने वाली दोषपूर्ण परिस्थितियों की व्याख्या कर सके।सवाल इस प्रकार हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“(1) प्रश्नः- क्या आपने गवाहों के साक्ष्य सुने हैं?जवाबः- हां।

(2) प्रश्नः- आपके खिलाफ सबूत है कि 31.5.15 पर आप X को टीवी देखने के बहाने अपने घर ले गए थे। आपको क्या कहना है?

जवाबः- नहीं साहब। (3) प्रश्नः- आपके खिलाफ यह भी सबूत है कि आप अपने घर को बंद करके भाग गए थे और बाद में ताला तोड़ दिया गया था और फिर एक्स का शव लकड़ी के खाट के नीचे पड़ा हुआ बरामद किया गया था।इस संबंध में आपका क्या कहना है?

जवाबः- नहीं साहब। (4) प्रश्नः- यह भी आपके खिलाफ सबूत में आया है कि आपने प्रीतम के साथ मिलकर एक्स की बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी।आपको क्या कहना है?

जवाबः- नहीं साहब, यह गलत है।"

31. तथापि, अपीलार्थी को कथित अपराध का दोषी ठहराने के उद्देश्य से, विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित अतिरिक्त परिस्थितियों पर विचार किया:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(क) पीडब्लू 3 द्वारा अपीलार्थी को ग्रिल और अपने कमरे के दरवाजे को बंद करते हुए देखने की परिस्थिति।

(ख) परिस्थिति कि अपीलार्थी ने पीडब्लू 3 को गलत जानकारी दी कि पीड़ित टीवी देखने के बाद पहले ही जा चुका था।

(ग) अभियुक्त द्वारा दरवाजा खोलने से इनकार करने की परिस्थिति क्योंकि उसके पास चाबी नहीं थी।

(घ) अपीलार्थी द्वारा हमला किए जाने के बाद ग्रामीणों को चाबियाँ देने की परिस्थिति।

(ङ) सह-अभियुक्त प्रीतम तिवारी द्वारा अपीलार्थी को शामिल करते हुए किए गए कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति की परिस्थिति।

32. निर्विवाद रूप से, निचली अदालत द्वारा भरोसा की गई उपरोक्त परिस्थितियों में से किसी को भी अपीलार्थी दोषी के सामने नहीं रखा गया था ताकि वह इसका उचित स्पष्टीकरण दे सके।

33. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 10 साल की एक निर्दोष लड़की को लालच दिया गया, बलात्कार किया गया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, हमने पूरे रिकॉर्ड को बहुत बारीकी से देखा।हमारा मन संदेह से भर गया।आखिरकार, हमने कुछ बहुत ही चौंकाने वाला देखा।हम इसके बाद जिस चौंकाने वाले पहलू पर चर्चा करेंगे, अगर हमारी ओर से भी किसी का ध्यान नहीं गया होता, तो यह न्याय की गंभीर विफलता का कारण बनता।

34. हमने सोचा कि आरोप पत्र के कागजात बुलाए जाएँ और पीडब्लू 2 किरण देवी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर गौर किया जाए; उनके द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और पीडब्लू 1 बबलू सॉ, और पीडब्लू 3 प्रिया कुमारी, पीड़ित की बड़ी बहन और पीडब्लू 2 (प्रथम मुखबिर) की बड़ी बेटी के पुलिस बयानों को आगे बढ़ाने के लिए सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज पीडब्लू 2 का आगे का बयान।एफ. आई. आर. और उपरोक्त गवाहों के पुलिस बयानों को पढ़कर हम हैरान रह गए।35. हम सबसे पहले पीडब्लू 2 द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से शुरुआत करते हैं जो इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“एस. आई. सह एस. एच. ओ. रीता कुमारी सबौर पी. एस. द्वारा नवल किशोर ओझा @फुचन पांडे के घर में दर्ज कराई गई किरण देवी का फरदबायन, जिसकी आयु अरविंद साह से लगभग 40 वर्ष थी, थतरी तोला, पुलिस स्टेशन-सबौर, जिला भागलपुर में 12 बजेः45 पी. एम

मेरा नाम किरण देवी है, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, पत्नी अरविंद साह, रियो थाटेरी तोला सबौर पुलिस स्टेशन-साबेर, जिला-भागलपुर।मैं आज 1 जून, 2015 को नवल किशोर (फुचन पांडे) के घर पर साबौर पुलिस स्टेशन के प्रभारी की उपस्थिति में बिना किसी दबाव के यह बयान दे रहा हूं कि कल 31 मई, 2015 को मैं अपनी दिवंगत बड़ी बहन सकिला देवी के घर जमुनिया परबत्ता में गया था।इस बीच, दोपहर करीब 12 बजे, मेरी बड़ी बेटी प्रिया 1037

कुमारी ने मुझे टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया कि मेरी छोटी बेटी, एक्स कहीं नहीं मिली है।फिर मैं तुरंत सबौर के लिए रवाना हो गया।जब मैं घर पहुँचा तो मेरी बड़ी बेटी प्रिया ने मुझे बताया कि एक्स मुन्ना पांडे के घर पर टीवी देखने गया था।जब वह सुबह 11 बजे तक वापस नहीं आई तो मेरी बड़ी बेटी ने मुझे फोन किया।जब मैं दसवें दिन मुन्ना पांडे के घर गया तो मैंने देखा कि मुन्ना पांडे के घर में ताला लगा हुआ था।हमने अपने रिश्तेदारों के साथ एक्स की तलाश शुरू की लेकिन एक्स कहीं नहीं मिला।जब मुन्ना पांडे को ताला खोलने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास चाबी नहीं है।फिर मैंने मुन्ना पांडे के भाई फुचन पांडे को फोन किया जो उनके ससुराल (ससुराल) में थे।

आज 1 जून, 2015 को नवल किशोर पांडे उर्फ फुचन पांडे दोपहर लगभग 12 बजे आए और उस कमरे का ताला खोला जहाँ यह पाया गया कि प्रीतम तिवारी, पुत्र दिलीप तिवारी निवासी शोभापुर, पुलिस स्टेशनःराजमहल, जिला कमरे के अंदर छिपा हुआ था।कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था।जब मुन्ना पांडे का कमरा खोला गया तो मेरी बेटी का शव बिस्तर के नीचे मिला।मुझे यकीन है कि प्रीतम तिवारी, पुत्र दिलीप तिवारी, निवासी शोभापुर, पुलिस स्टेशनःराजमहल जिला साहेबगंज और मुन्ना पांडे पुत्र स्वर्गीय बीर बहादुर पांडे पुत्र ठटकरी तोला, पुलिस स्टेशनःसाबौर, जिला भागलपुर ने संयुक्त रूप से साजिश रची और मेरी 11

साल की बेटी (एक्स) के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसके शव को कमरे में छिपा दिया।

यह मेरा बयान है जिसे मैंने सुना और समझने के बाद उन्हें पढ़ने के बाद मैंने उपरोक्त बयानों को सही पाया और मैं अपनी बहन के बेटे, बबलू साह पुत्र सतीश साह निवासी जमुनिया, तोना पर्वत (नवघचिया) भागलपुर की उपस्थिति में अपनी वसीयत से अपने हस्ताक्षर कर रहा हूं।"

(जोर दिया गया) 36।पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किरण देवी का आगे का बयान इस प्रकार हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“इस मामले की आगे की जांच में, पुलिस ने इस मामले की शिकायतकर्ता-किरण देवी, लगभग 40 वर्ष की आयु, पत्नी-अरविंद साह, पत्नी-थथेरी तोला, पीएस-सबौर, जिला-भागलपुर का बयान फिर से दर्ज किया।एफ. आई. आर. के साथ सहमति जताते हुए, उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनके घर के सामने के पड़ोस में दो भाई रहते थे-मुन्ना पांडे।

और नवल किशोर ओझा @फुचन पांडे।वे दोनों एक-एक कमरे में रहते हैं।दोनों भाइयों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिसके कारण नवल किशोर ओझा उर्फ फुचन पांडे अपने ससुराल (ससुराल) में रहता था और मुन्ना पांडे, सबौर काली स्थान के पास किराए के मकान में रहता था।फुचन पांडे ने अपना कमरा रखरखाव के लिए अपने बहनोई (पत्नी के भाई) को सौंप दिया था। प्रीतम तिवारी एक कपड़े की दुकान में काम करते थे।कपड़ों की दुकान के लोग भी कभी-कभी फुचन पांडे के घर आते थे।फुचन पांडे के घर में एक टीवी था।पड़ोस के बच्चे भी टीवी देखने के लिए उनके घर आते थे। आई. डी. 1 की तारीख को मैं (किरण देवी) जमुनिया पर्वत में अपनी दिवंगत बहन शकीला देवी के घर गई थी।तारीख 31.05.15 पर लगभग 12 बजेः00, उनकी बड़ी बेटी प्रिया कुमारी ने उन्हें टेलीफोन पर सूचित किया कि उनकी छोटी बेटी एक्स कहीं नहीं मिली।वह तुरंत वहाँ से चली गई। साबौर में अपने घर पहुंचने के बाद, उसकी बड़ी बेटी ने बताया कि उसकी छोटी बेटी एक्स ने कहा था कि वह टीवी देखने के लिए प्रीतम तिवारी के घर जा रही थी। प्रीतम तिवारी ने लगभग 9 बजे अपने घर पर टीवी देखने के लिए एक्स को फोन किया था।जब एक्स ग्यारह बजे तक घर नहीं आया, तो उसकी बड़ी बेटी प्रिया उसे खोजने के लिए प्रीतम तिवारी के घर गई।उस समय प्रीतम तिवारी दरवाजा बंद कर रहे थे।जब उसने प्रीतम तिवारी से एक्स का ठिकाना पूछा, तो उसने बताया कि वह वहाँ नहीं थी। उसके बाद वह उसे खोजने के लिए आम के बगीचे में गई।वह वहाँ भी नहीं मिली।फिर प्रिया ने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया और उसकी तलाश करने गई, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं ढूंढ सकी।इतनी गहन खोज के बाद भी एक्स कहीं नहीं मिला। इसलिए हम सभी ने सामूहिक रूप से प्रीतम तिवारी को पकड़ने का फैसला किया, जो भी नहीं मिला।ग्रामीणों को संदेह हुआ इसलिए उन सभी ने मुन्ना पांडे को बुलाया और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा।लेकिन मुन्ना पांडे ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास ताला की चाबी नहीं है।इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने नवल पांडे उर्फ फुचन पांडे को फोन किया।उस समय वे शोभाबुर में अपने ससुर के घर पर थे।जब मुन्ना पांडे ने चाबियाँ सौंपने से इनकार कर दिया, तो सभी को संदेह हो गया कि प्रीतम तिवारी वहाँ नहीं है और यह बहुत संभव था कि उसने (प्रीतम तिवारी) उसकी बेटी के साथ कुछ घटना की हो।1-06-2015 को नवल किशोर ओझा @फुचन पांडे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आए और लगभग 12 बजे ग्रिल का ताला खोला।00 दोपहर।

जब ताला खोला गया तो सभी ग्रामीण बरामदे में घुस गए और जब फुचन पांडे के कमरे की खिड़की से देखा तो प्रीतम तिवारी को कमरे में पालंग (लकड़ी की खाट) पर सोते हुए पाया।जब फुचन पांडे ने अपने कमरे का ताला खोला तो प्रीतम तिवारी लकड़ी के बिस्तर के नीचे छिपने लगे।ग्रामीणों ने उसे बिस्तर से बाहर निकाला और एक्स का ठिकाना पूछना शुरू कर दिया। शुरू में उसने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया।लेकिन जब सभी लोगों ने उनसे सख्ती से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक्स (मृतक) मुन्ना पांडे के घर में था।और जब सभी लोगों ने मुन्ना पांडे के दरवाजों के ताले तोड़कर कमरे के अंदर देखा तो उन्हें कमरे में पालंग (लकड़ी की खाट) के नीचे ग्यारह साल की बेटी एक्स का शव पड़ा मिला।जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो वह पहले ही मर चुकी थी।हमने उसका चेहरा बेहद सूजा हुआ पाया, दोनों होंठ सूजे हुए थे, उसके दाहिने गाल पर खून के धब्बे देखे गए थे।उसके कपड़े (अवैध) तरीके से थे।मृतक एक्स के गुप्तांग सूजे हुए थे और खून से सने घाव और मल से चिपके हुए गुदा सूजे हुए पाए गए थे।उन्होंने आगे बताया कि प्राथमिकी में नामित दोनों आरोपी व्यक्तियों-(1) प्रीतम तिवारी, पुत्र-दिलीप तिवारी, पुत्र-शोभापुर, पुत्र-राजमहल, जिला-साहेबगंज, राज्य-झारखंड, वर्तमान पता नवल किशोर ओझा, पुत्र-साबौर, जिला-भागलपुर, (2) मुन्ना पांडे, पुत्र-स्वर्गीय बीर बहादुर पांडे, पुत्र-थथेरी, पुत्र-साबौर, पुत्र-साबौर, पुत्र-साबौर, जिला-भागलपुर ने अपनी ग्यारह

वर्षीय बेटी एक्स (मृतक) के साथ बलात्कार किया और सबूत हटाने के उद्देश्य से भागलपुर में बलात्कार किया।उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को पालंग (लकड़ी की खाट) के नीचे छिपा दिया।ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।इसके अलावा उन्होंने कोई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बताए।"

(जोर दिया गया) 37।पीडब्लू 1 बबलू सॉ का पुलिस बयान इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“इस मामले की आगे की जांच में बबलू साह, पुत्र सतीश साह, पुत्र जमुनिया, थाना-परवट्टा, जिला-खगड़िया का गवाह बयान दर्ज किया गया, जिसमें घटना के पूर्ण समर्थन के साथ अपने बयान में बताया गया कि मृतक एक्स उसकी चाची (उसकी मां की बहन) की बेटी है।तारीख 31.05.15 मृतक की माँ उसके घर आई।मृतक एक्स की बड़ी बहन प्रिया ने अपनी माँ को टेलीफोन पर सूचित किया

कि उसके पड़ोसी नवल किशोर ओझा के बहनोई (पत्नी के भाई) प्रीतम तिवारी ने एक्स को उसके घर पर टेलीविजन देखने के लिए फोन किया और वह घर नहीं लौटी थी।सूचना पर, वह अपनी मौसी (माँ की बहन), किरण देवी के साथ सबौर आया और परिवार के सदस्यों के साथ और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आस-पास के स्थानों पर पूरी खोजबीन की, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल सका।तलाशी के दौरान जब मैं नवल किशोर ओझा के घर गया तो मैंने देखा कि उनके घर में ताला लगा हुआ है।कुछ लोगों को संदेह था कि प्रीतम तिवारी उसे कहीं ले गया था या कमरे के अंदर है, क्योंकि बल्ब की रोशनी उसके घर से प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी।फिर सभी लोगों ने मुन्ना पांडे को फोन किया और उसे ताला खोलने के लिए कहा, जिस पर उसने मना कर दिया और बहाना बनाया कि उसके पास चाबी नहीं है।फिर सभी लोगों का संदेह और बढ़ गया।तब ग्रामीणों ने मुन्ना पांडे के भाई नवल किशोर ओझा उर्फ फुचन पांडे को टेलीफोन पर घटना की सूचना दी।फोन के समय फुचन पांडे शोभाबुर में अपने ससुराल में थे।वह पिछले दो महीने से यहां नहीं रह रहा था।तारीख 01.06.15 पर लगभग 12 बजे:00 दोपहर में, फुचन पांडे अपने परिवार के साथ आए और घर का ताला खोला और प्रीतम तिवारी को अपने घर में छिपा हुआ देखा।जब स्थानीय लोगों ने मृतक लड़की एक्स के बारे में सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया कि एक्स (मृतक) मुन्ना पांडे के घर में था और फिर उसने भागने की कोशिश की।फिर सभी लोगों ने मुन्ना पांडे के कमरे के दरवाजे का ताला तोड़ दिया और जब उन्होंने अंदर देखा तो एक्स का शव बिस्तर (लकड़ी की खाट) के नीचे पड़ा मिला।उसके शरीर पर कपड़े अव्यवस्थित स्थिति में थे।गाँव की महिलाओं ने बताया कि एक्स (मृतक) के गुप्तांगों के आसपास बहुत सारे खून के धब्बे और सूजन पाई गई थी।मृतक एक्स का चेहरा बेहद सूजा हुआ था, दोनों होंठों पर खून के धब्बे थे जो सूजन के बाद लटके हुए थे।उन्होंने आगे कहा कि दोनों आरोपी व्यक्ति हैं।एफ. आई. आर. में नामित लड़की को टीवी देखने के बहाने बुलाया गया और उसके साथ बलात्कार किया और सबूत छिपाने के लिए उसका गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी और शव को पालंग (लकड़ी की खाट) के नीचे छिपा दिया।इसके बाद स्थानीय थाने को घटना की सूचना दी गई।पुलिस आई और आगे की कार्रवाई शुरू की।उन्होंने आगे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं बताई।"

(बल दिया गया)

1041

38. पीड़ित की बड़ी बहन, पीडब्लू 3 प्रिया कुमारी का पुलिस बयान इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“इस मामले की आगे की जांच में मैंने गवाह प्रिया कुमारी का बयान दर्ज किया, जिनकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, पुत्र-अरविंद साह, निवासी-थथेरी, तोला पीएस-सबौर, जिला भागलपुर।एफ. आई. आर. को प्रमाणित करने के बाद, उसने अपने बयान में बताया कि तारीख 31.05.15 पर वह अपने घर में खाना बना रही थी।उनकी माँ किरण देवी पार्वती में अपनी चाची (उनकी माँ की बहन) के घर गई थीं।उसके पिता गुजरात में मजदूर के रूप में काम करते हैं।घर में और कोई नहीं था।लगभग 09 बजे:00 उसकी छोटी बहन मृतक एक्स टीवी देखने के लिए फुचन पांडे के घर गई थी। (पत्नी की बहन) फुचन पांडे के बहनोई प्रीतम तिवारी उस घर में रहते थे।उसने अपने घर पर टीवी देखने के लिए एक्स को फोन किया था।जब एक्स दो घंटे बाद भी वापस नहीं आया, तो प्रिया (बड़ी बहन) उसे फोन करने के लिए प्रीतम तिवारी के कमरे में गई।प्रीतम तिवारी से एक्स के ठिकाने के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि एक्स वहां नहीं आया था।उस समय प्रीतम बरामदे की ग्रिल को बंद कर रहा था।फिर वह उसे खोजने के लिए पास के आम के बगीचे में गई।वहाँ भी उसने उसे नहीं देखा।अंत में उसने अपनी माँ को फोन किया और उसे

सूचित किया कि एक्स लापता है।किरण देवी के आने पर सभी ने अपने सभी रिश्तेदारों के घर पर एक्स की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कहीं भी ढूंढ नहीं सके।कुछ लोगों को संदेह था कि एक्स प्रीतम तिवारी के साथ था।फिर सभी ने प्रीतम तिवारी की तलाश शुरू कर दी।वह भी कहीं नहीं मिला।फिर सभी ग्रामीणों और उनके रिश्तेदारों ने मुन्ना पांडे को घर खोलने के लिए कहा लेकिन मुन्ना पांडे ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और बहाना बनाया कि उनके पास चाबी नहीं है।फिर ग्रामीणों ने मुन्ना पांडे के भाई फुचन पांडे को फोन किया लेकिन उन्होंने पाया कि फुचन पांडे पिछले दो महीनों से राजमहल में अपने ससुर के घर (ससुराल) में रह रहा था।तारीख 01.06.15 पर लगभग 12 बजे:00 शाम को नवल किशोर ओझा @फुचन पांडे आए और अपनी जांच का ताला खोला।

(जोर दिया गया) 39।इस प्रकार, पुलिस के सामने सभी गवाहों का मामला यह था कि यह प्रीतम तिवारी ही थे जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन और तारीख को पीड़ित के घर आए थे और पीड़ित को अपने साथ टीवी देखने के लिए अपने घर ले गए थे। सभी बयानों से आगे पता चलता है कि यह प्रीतम तिवारी थे जो पाए गए थे

जब गवाहों ने प्रीतम तिवारी से पीड़ित के ठिकाने के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया।

40. न तो बचाव पक्ष के वकील और न ही लोक अभियोजक और न ही निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी और दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने भी मामले के उपरोक्त पहलू पर गौर करने और सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करने के बारे में नहीं सोचा।

41. बचाव पक्ष के वकील का कर्तव्य था कि वह गवाहों का उनके पुलिस बयानों के साथ सामना करे ताकि भौतिक चूक के रूप में विरोधाभासों को साबित किया जा सके और उन्हें रिकॉर्ड पर लाया जा सके।हमें यह कहते हुए खेद है कि विद्वान बचाव पक्ष के वकील को यह पता नहीं था कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 145 के अनुसार किसी गवाह को उसके पुलिस बयानों के साथ कैसे विरोधाभासी बनाया जाए।

42. लोक अभियोजक की ओर से चूक भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।लोक अभियोजक को पता था कि गवाह सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयानों में पुलिस के सामने जो कहा था, उसके विपरीत कुछ बयान दे रहे थे। यह उनका कर्तव्य था कि वे गवाहों के ध्यान में लाएँ और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किए बिना भी उनका सामना करें।

43. ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी भी मूक दर्शक बने रहे।साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन गवाहों से प्रासंगिक प्रश्न पूछना पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य था। सी. आर. पी. सी. की धारा 162 एक न्यायाधीश को पुलिस जांच के रिकॉर्ड को देखने से नहीं रोकती है।बलात्कार और हत्या का मामला होने के कारण और साक्ष्य संदेह से मुक्त नहीं होने के कारण, विचारण न्यायाधीश को न्याय के हित में, महत्वपूर्ण सामग्री और पुलिस जांच के दौरान अभियोजन पक्ष के एकमात्र महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा कही गई बातों से भी परिचित होना चाहिए था।यदि उसने ऐसा किया होता, तो वह बिना किसी अनुचितता के इन गवाहों द्वारा जांच अधिकारी को दिए गए बयानों और मुकदमे में उनके साक्ष्य के बीच विसंगतियों को पकड़ सकता था, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत गवाहों से सवाल पूछकर रिकॉर्ड में लाया जा सकता था। हमारी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी विचारण न्यायाधीश को, अभियोजन या बचाव पक्ष से अलग, अभियोजन पक्ष के गवाहों को अन्यथा अनुमेय प्रश्न पूछने से रोक सके, यदि न्याय स्पष्ट रूप से इस तरह के पाठ्यक्रम की मांग करता है।वर्तमान मामले में, हमारी दृढ़ता से राय है कि न्याय के हित में, विचारण न्यायाधीश 1043

ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पुलिस जांच के रिकॉर्ड को तब तक नहीं देखा जब तक कि जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई और गवाह के रूप में बरी नहीं कर दिया गया।इस स्तर पर भी, विचारण न्यायाधीश अधिकारी और अन्य गवाहों को वापस बुला सकता था और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से उनसे पूछताछ कर सकता था। यह खेदजनक है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

44. हम उपरोक्त को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझाने के इस अवसर का उपयोग करते हैं।

45. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"धारा **162**।पुलिस को दिए गए बयानों पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिएःबयानों का उपयोग

सबूत में।– (1) इस अध्याय के तहत जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान पर, यदि वह लिखित ही रह जाता है, तो उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे; और न ही ऐसा कोई बयान या उसका कोई रिकॉर्ड, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे बयान या रिकॉर्ड का कोई हिस्सा, किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसके बाद, उस समय जब ऐसा बयान दिया गया था, जांच के तहत किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी जांच या मुकदमे में, जब ऐसा बयान दिया गया थाःबशर्ते कि जब किसी गवाह को ऐसी जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है, जिसका बयान उपरोक्त के रूप में लिखित रूप में कम कर दिया गया है, तो उसके बयान का कोई भी हिस्सा, यदि विधिवत साबित हो जाता है, तो अभियुक्त द्वारा और अदालत की अनुमति से, अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे गवाह का खंडन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है; और जब ऐसे बयान का कोई भी हिस्सा इस तरह से उपयोग किया जाता है, तो उसके किसी भी हिस्से का उपयोग ऐसे गवाह की पुनः परीक्षा में भी किया जा सकता है, लेकिन केवल उसकी प्रतिपरीक्षा में संदर्भित किसी भी मामले को समझाने के उद्देश्य से।

(2) इस धारा की कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के भीतर आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं मानी जाएगी; या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करने के लिए।

स्पष्टीकरण.--उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति को बताने में चूक विरोधाभास के समान हो सकती है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सार्थक और अन्यथा प्रासंगिक नहीं प्रतीत होता है जिसमें ऐसी चूक होती है और क्या कोई चूक विशेष संदर्भ में विरोधाभास के बराबर है, यह तथ्य का प्रश्न होगा।"

46. धारा 162 सी. आर. पी. सी. में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जांच के दौरान पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, चाहे वह दर्ज किया गया हो या नहीं, इस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि धारा के पहले परंतुक में प्रावधान किया गया है।प्रथम परंतुक में कहा गया है कि जब कोई गवाह, जिसका बयान पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में कम कर दिया गया है, को जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है, तो अदालत की अनुमति से आरोपी साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से गवाहों का खंडन कर सकता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि धारा 162 का पहला भाग किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष गवाह के बयान के उपयोग को किसी भी उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित करता है, इसके अलावा कि बाद में परंतुक में प्रावधान किया गया है, और जैसा कि परंतुक कहता है कि न्यायालय अभियुक्त को अपने पिछले बयान के साथ गवाह का खंडन करने की अनुमति दे सकता है, इसलिए न्यायालय को स्वतः कुछ भी करने की कोई शक्ति नहीं है।हमारी राय में, यह खंड का गलत अध्ययन होगा।धारा 162 के पहले भाग में कहा गया है कि जांच के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए बयान का उपयोग परंतुक में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।हम "उद्देश्य" शब्द पर जोर देते हैं।परंतुक में उल्लिखित उद्देश्य ऐसे गवाह द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए पिछले बयान का उपयोग करके अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा राज्य के पक्ष में दिए गए साक्ष्य का खंडन करना है।इसका उद्देश्य राज्य की ओर से एक गवाह द्वारा अभियोजन पक्ष के पक्ष में दिए गए साक्ष्य को बदनाम करना है।यह धारा इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कथन के उपयोग को प्रतिबंधित करती है।यह नहीं कहता कि बयान का उपयोग केवल आरोपी के अनुरोध पर किया जा सकता है।धारा 162 सी. आर. पी. सी. के पहले भाग में लगाई गई सीमा या प्रतिबंध इस उद्देश्य से संबंधित है जिसके लिए कथन का उपयोग किया जा सकता है; यह उस प्रक्रिया से संबंधित नहीं है जिसे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाया जा सकता है।सीमित उद्देश्य को निर्धारित करने वाले परंतुक में उस तरीके का भी उल्लेख है जिसमें एक अभियुक्त व्यक्ति पुलिस को दिए गए अपने पिछले बयान के साथ गवाह का खंडन कर सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से उस शक्ति को छीनने का तात्पर्य नहीं है जो किसी भी दस्तावेज को देखने के लिए न्यायालय में निहित है, जिसे वह न्याय के उद्देश्यों को देखने और ऐसे प्रश्नों को एक गवाह के सामने रखने के लिए आवश्यक समझता है जो वह सच्चाई को उजागर करने के लिए आवश्यक समझता है।हम महसूस करते हैं कि परंतुक न्यायालय को जांच के

दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए बयानों का उपयोग परंतुक में उल्लिखित किसी अन्य उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने से रोकेगा, लेकिन यह किसी अन्य तरीके से उस शक्ति को लागू नहीं करता है जो न्यायालय में दस्तावेजों को देखने या गवाहों से खुद ही सवाल करने के लिए निहित है।हमें यह कहना बेतुका लगता है कि 1045

एक न्यायाधीश एक गवाह के सामने एक प्रश्न नहीं रख सकता है जिसे एक पक्ष रख सकता है।इस संबंध में हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के प्रावधानों का उल्लेख करेंगे, जहां गवाहों से सवाल पूछने और दस्तावेजों को देखने के लिए न्यायाधीश को बहुत व्यापक शक्तियों के साथ कपड़े पहनने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है और इसके लिए प्रावधान किया गया है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 यह कहती हैः—

"धारा **165**।प्रश्न पूछने या प्रस्तुत करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति।—

न्यायाधीश, प्रासंगिक तथ्यों का उचित प्रमाण खोजने या प्राप्त करने के लिए, किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी गवाह या पक्षकारों से किसी भी प्रासंगिक या अप्रासंगिक तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और किसी भी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने का आदेश दे सकता है और न तो पक्षकारों और न ही उनके एजेंटों को ऐसे किसी प्रश्न या आदेश पर कोई आपत्ति करने का अधिकार होगा, न ही अदालत की अनुमति के बिना, ऐसे किसी प्रश्न के उत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी गवाह से जिरह करने का अधिकार होगाः..."

47. सी. आर. पी. सी. की धारा 162 में हमारी राय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक विचारण न्यायाधीश को स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोप पत्र के कागजातों को देखने से रोकता है और स्वयं उस व्यक्ति के बयान का उपयोग करने से रोकता है जिसकी जाँच पुलिस ने उसमें दर्ज की है, जब वह अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में राज्य के पक्ष में साक्ष्य देता है।न्यायाधीश ऐसा कर सकता है या वह अभियुक्त के वकील को अभिलिखित बयान दे सकता है ताकि वह इसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए कर सके। हम इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि कई सत्र मामलों में जब न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई अधिवक्ता उपस्थित होता है और विशेष रूप से जब एक कनिष्ठ अधिवक्ता, जिसे न्यायालय की प्रक्रिया का अधिक अनुभव नहीं है, को किसी अभियुक्त व्यक्ति का बचाव करने के लिए नियुक्त किया गया है, तो पीठासीन न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के वैधानिक प्रावधानों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करे, जैसा कि तारा सिंह बनाम राज्य ने ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 441 में बताया है और किसी भी न्यायालय को गवाह को लिखित में पिछले बयान के संदर्भ में विरोधाभासी होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए या जब तक कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है।यह संभव है कि यदि गवाह का ध्यान इन भागों की ओर आकर्षित किया जाता है जिनके संदर्भ में उसका खंडन करने का प्रस्ताव है, तो वह पूरी तरह से संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में सक्षम हो सकता है और उस स्थिति में पिछले कथन का वह भाग जो अन्यथा विरोधाभासी होगा, अब गवाह की गवाही का खंडन या चुनौती नहीं देगा।

48. हमारी राय में, वर्तमान विवरण के मामले में जहां किसी न्यायालय में दिए गए साक्ष्य में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनका प्रथम सूचना रिपोर्ट या पुलिस के बयानों में उल्लेख नहीं है, परीक्षण न्यायाधीश के लिए यह हमेशा सलाह दी जाती है और यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वह पुलिस के दस्तावेजों को देखे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या परीक्षण में गवाहों द्वारा फंसाये गए व्यक्तियों को उनके द्वारा जांच के दौरान फंसाया गया था।

49. उपरोक्त संदर्भ में, हम तीन न्यायाधीशों का उल्लेख कर सकते हैं और उन पर भरोसा कर सकते हैं

वी. के. मिश्रा बनाम उत्तराखंड राज्य, (2015) के मामले में न्यायपीठ का निर्णय

9 एस. सी. सी. 588, जिसमें इस न्यायालय ने सी. आर. पी. सी. की धारा 161 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 पर उचित विचार करने के बाद निम्नानुसार टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“16. सी. आर. पी. सी. की धारा 162 पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान के उपयोग को प्रतिबंधित करती है, सिवाय ऐसे गवाहों के विरोधाभास के सीमित उद्देश्य के, जैसा कि वहां संकेत दिया गया है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (1) के तहत पुलिस के समक्ष एक गवाह द्वारा दिए गए बयान का उपयोग केवल उस गवाह का खंडन करने के उद्देश्य से किया जा सकता है जो उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 (1) के प्रावधान में मुकदमे में कहा है। जाँच के दौरान दर्ज किए गए धारा 161 सी. आर. पी. सी. के तहत बयान सबूत के ठोस टुकड़े नहीं हैं, लेकिन इनका उपयोग मुख्य रूप से सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता हैः((i) साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत किसी अभियुक्त द्वारा ऐसे गवाह का खंडन करना; (ii) अभियोजन पक्ष द्वारा भी लेकिन न्यायालय की अनुमति के साथ ऐसे गवाह का खंडन करना; और (iii) यदि आवश्यक हो तो गवाह से फिर से पूछताछ करना।

17. अदालत स्वतः ही पुलिस को दिए गए बयानों का उपयोग नहीं कर सकती है जो साबित नहीं हुए हैं और उनके संदर्भ में ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकती है जो अदालत में गवाह की गवाही से असंगत हैं।धारा 162 सी. आर. पी. सी. के शब्द "यदि विधिवत साबित होते हैं" स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि गवाहों के बयान के रिकॉर्ड को सीधे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और न ही इस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन गवाह से प्रतिपरीक्षा के दौरान और जांच अधिकारी की प्रतिपरीक्षा के दौरान भी गवाह से प्रवेश प्राप्त करके विरोधाभास के उद्देश्य से उन्हें विधिवत साबित किया जाना चाहिए।जाँच अधिकारी के समक्ष बयान का उपयोग विरोधाभास के लिए किया जा सकता है, लेकिन केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के सख्त अनुपालन के बाद जो विरोधाभास के लिए अभिप्रेत भागों की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

1047

मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1048 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 इस प्रकार हैः“145.लिखित रूप में पिछले बयानों के रूप में प्रतिपरीक्षा।—एक गवाह से लिखित रूप में उसके द्वारा दिए गए पिछले बयानों के बारे में जिरह की जा सकती है या लिखित में घटाई जा सकती है, और प्रश्नगत मामलों के लिए प्रासंगिक हो सकती है, बिना उसे ऐसा लेखन दिखाए या साबित किए बिना; लेकिन, यदि इसका उद्देश्य लेखन द्वारा उसका खंडन करना है, तो लेखन को साबित करने से पहले उसका ध्यान उसके उन हिस्सों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिनका उपयोग उसका खंडन करने के उद्देश्य से किया जाना है।"

19. साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत जब गवाह के पिछले बयान को लिखित में घटाकर उसका खंडन करने का इरादा है, तो ऐसे गवाह का ध्यान उसके उन हिस्सों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए, जिनका उपयोग लेखन का उपयोग करने से पहले उसका खंडन करने के उद्देश्य से किया जाना है।एक गवाह के बयान को दर्ज करते समय, यह सुनिश्चित करना निचली अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि पुलिस के बयान के जिस हिस्से के साथ गवाह का खंडन करने का इरादा है, उसे गवाह की जिरह में उसके ध्यान में लाया जाए।गवाह का ध्यान उस भाग की ओर आकर्षित किया जाता है और इसे पुनः प्रस्तुत करके उसकी प्रतिपरीक्षा में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।यदि गवाह उस भाग को स्वीकार करता है जिसका उद्देश्य उसका खंडन करना है, तो यह साबित हो जाता है और विरोधाभास के और सबूत की आवश्यकता नहीं है और सबूत की सराहना करते हुए इसे पढ़ा जाएगा।यदि वह बयान के उस हिस्से को देने से इनकार करता है, तो उसका ध्यान उस बयान की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए और बयान में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।इस प्रक्रिया से विरोधाभास को केवल रिकॉर्ड में लाया जाता है, लेकिन यह अभी तक साबित नहीं हुआ है।इसके बाद जब जाँच अधिकारी की अदालत में जाँच की जाती है, तो उसका ध्यान विरोधाभास के उद्देश्य से चिह्नित मार्ग की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए, यह तब जाँच अधिकारी के बयान में साबित होगा जो फिर से पुलिस बयान का उल्लेख करके गवाह के बारे में गवाही देगा।इस प्रक्रिया में फिर से पुलिस के बयान का उल्लेख करना और उस हिस्से को निकालना शामिल है जिसके साथ बयान के निर्माता का खंडन करने का इरादा था।यदि गवाह का सामना बयान के उस हिस्से से नहीं किया गया था जिसके साथ बचाव पक्ष उसका खंडन करना चाहता था, तो अदालत स्वतः ही पुलिस को दिए गए बयानों का उपयोग नहीं कर सकती है जो धारा 145 के अनुपालन में साबित नहीं हुए हैं।

साक्ष्य अधिनियम जो विरोधाभास के लिए अभिप्रेत भागों की ओर ध्यान आकर्षित करके है।

(जोर दिया गया) 50।इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में जो ध्यान देने योग्य है वह कानून का सिद्धांत है कि यदि गवाह का सामना बयान के उस हिस्से से नहीं किया गया था जिसके साथ बचाव पक्ष उसका खंडन करना चाहता था, तो न्यायालय स्वतः ही पुलिस को दिए गए बयानों का उपयोग नहीं कर सकता है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अनुपालन में साबित नहीं हुए हैं। इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार भौतिक चूक के रूप में सभी प्रमुख विरोधाभासों को साबित करना और उन्हें रिकॉर्ड पर लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।ऐसा करना बचाव पक्ष के वकील का कर्तव्य है।

51. इस न्यायालय ने (1974) 4 में रघुनाथन बनाम यू. पी. राज्य मामले में रिपोर्ट की

एस. सी. सी. 186 में यह देखा गयाः-(एस. सी. सी. पी. 191, पैरा 16)

“16. हम अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 की भाषा, हालांकि व्यापक है, स्पष्ट या विशिष्ट नहीं है जो किसी गवाह से पूछताछ करने के लिए न्यायालय की व्यापक और विशेष शक्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध का विस्तार करने के लिए पर्याप्त है, जो न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 द्वारा स्पष्ट और स्पष्ट रूप से दी गई है।....इसलिए, हम मानते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत न्यायालय की विशेष शक्तियों को बाधित नहीं करती है।

(बल दिया गया)

52. दांडू लक्ष्मी रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य, (1999) 7 में यह न्यायालय

एस. सी. सी. 69, यह आयोजित किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“20. अब यह याद रखना चाहिए कि उक्त प्रक्रिया का पालन केवल तभी किया जा सकता है जब कोई गवाह बक्से में हो। उपरोक्त दो तरीकों को छोड़कर, संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया बयान केवल उस संबंध में मुकदमे के सभी चरणों में ही दर्ज किया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, यदि अदालत ने संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान के संदर्भ में गवाह से कोई सवाल नहीं किया है, तो अदालत के लिए उस बयान का उपयोग बाद में उस गवाह के साक्ष्य के संबंध में कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए भी करने की अनुमति नहीं है।

1049

मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1050 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

संसद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जिस पर रोक लगाई जाती है, उसे किसी भी अप्रत्यक्ष तरीके से रोका नहीं जा सकता है।"

(जोर दिया गया) 53।सरकार (1999,15 वां पृष्ठ 2319 आदि)यह कहता है कि एक न्यायाधीश को सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछने में सक्रिय भूमिका निभाने और गवाहों की अयोग्य परीक्षा से उत्पन्न होने वाले संदेह, यदि कोई हो, को दूर करने का अधिकार है।लेकिन, जैसा कि कहा गया है

लॉर्ड डेनिंग द्वारा जोन्स बनाम राष्ट्रीय कोयला बोर्ड, 1957 (2) ऑल ई. आर. 155

(सी. ए.), न्यायाधीश "एक न्यायाधीश का कवच गिराकर एक अधिवक्ता का वस्त्र धारण नहीं कर सकता है।"

54. बेशक, न्यायाधीश को एक निष्क्रिय दर्शक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए जैसा कि फिपसन द्वारा जोर दिया गया है (साक्ष्य, 1999,15 वीं संस्करण, पैरा 1.21 निम्नानुसारः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“जब अंग्रेजी मुकदमे के रूप ने अपना आधुनिक संस्थागत रूप ग्रहण किया, तो न्यायाधीश की भूमिका एक तटस्थ अंपायर की थी।आपराधिक मामलों में अभी भी व्यापक रूप से यही स्थिति है।दीवानी मामलों में, कुछ असाधारण मामलों को छोड़कर जूरी परीक्षण को छोड़ने से इस सिद्धांत में कुछ कमी आई।1999 में सिविल प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों के थोक परिवर्तनों ने आधुनिक न्यायाधीश की हस्तक्षेपवादी भूमिका पर जोर दिया है।जबकि औपचारिक रूप से न्यायाधिकरण एक प्रतिक्रियाशील न्यायाधीश था (पिछली सदियों से अंग्रेजी सामान्य कानून के केंद्र में-स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा) इसके बजाय हमारे पास एक सक्रिय न्यायाधीश होगा जिसका कार्य प्रारंभिक चरण में कार्रवाई का प्रभार लेना और इसके संचालन का प्रबंधन करना होगा।"

(बल दिया गया)

55. राजस्थान राज्य बनाम अनी @हनीफ और अन्य में यह न्यायालय। (1997)

6 एस. सी. सी. 162 ने निम्नलिखित रूप में बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण अवलोकन किएः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“11. ... साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 निचली अदालत को प्रासंगिक तथ्यों की खोज करने के लिए "किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी गवाह, या पक्षकारों से, किसी भी तथ्य के बारे में प्रासंगिक या अप्रासंगिक" कोई भी सवाल पूछने के लिए विशाल और अप्रतिबंधित शक्तियां प्रदान करती है।उक्त धारा को "कोई भी" शब्द के साथ भव्य रूप से जोड़कर तैयार किया गया था, जो केवल निचली अदालत को जब भी आवश्यक लगे, शक्ति का उपयोग करने के लिए बेलगाम शक्ति प्रदान करने के विधायी इरादे से प्रेरित हो सकता था।

सच को उजागर करें।भले ही ऐसा कोई भी प्रश्न अपरिवर्तनीयता में बदल जाता है, लेकिन यह अदालत की शक्तियों के दायरे से परे नहीं जाएगा।यह धारा 165 में "प्रासंगिक या अप्रासंगिक" शब्दों से स्पष्ट है।किसी भी पक्ष को इस तरह के किसी भी प्रश्न पर आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है।12. कई परिस्थितियों में अवकाश अच्छा हो सकता है, लेकिन मुकदमे के दौरान एक न्यायाधीश का मूक रहना एक आदर्श स्थिति नहीं है।एक मौन न्यायाधीश जनता के दिमाग में कैरिकेटेड मॉडल हो सकता है। लेकिन मुकदमे के दौरान उसके सक्रिय या गतिशील होने में कुछ भी गलत नहीं है ताकि आपराधिक न्याय अंत में प्राप्त किया जा सके।आपराधिक मुकदमा दो प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच एक मुकाबला या मुकाबला नहीं होना चाहिए जिसमें न्यायाधीश केवल एक दर्शक की भूमिका निभाता है या यहां तक कि एक अंपायर भी यह घोषित करने के लिए कि दौड़ कौन जीता है।एक न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह मुकदमे में सक्रिय रूप से भाग लेगा, उचित संदर्भ में गवाहों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करेगा जो वह सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक समझता है।ऐसा कुछ भी नहीं है जो गवाहों से सवाल पूछने की उनकी शक्ति को रोकता है, या तो मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के दौरान या यहां तक कि सच्चाई को उजागर करने के लिए पुनः परीक्षा के दौरान भी।इसका परिणाम यह है कि यदि किसी न्यायाधीश को लगता है कि किसी गवाह ने कोई त्रुटि या चूक की है तो यह पता लगाना न्यायाधीश का कर्तव्य है कि क्या ऐसा था, क्योंकि गलती करना मानवीय है और जिरह के दौरान घबराहट के तनाव में गलती की संभावना बढ़ सकती है।आपराधिक न्याय साक्ष्य-संग्रह प्रक्रिया के दौरान गवाहों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर आधारित नहीं होना चाहिए।ट्रायल जज के लिए सक्रिय और सतर्क रहना एक उपयोगी अभ्यास है ताकि त्रुटियों को कम किया जा सके।(बल दिया गया)

56. उपरोक्त संदर्भ में, टिप्पणियों को उद्धृत करना उचित है

चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. राम चंदर बनाम हरियाणा राज्य, (1981) 3 एस. सी. सी.

191:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“2. विचारण की प्रतिकूल प्रणाली जो कुछ भी है, एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है कि एक परीक्षण की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश एक रेफरी या एक अंपायर की भूमिका निभाते हैं और परीक्षण को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच एक प्रतियोगिता में विकसित करने की अनुमति देते हैं, जिसमें परीक्षण प्रक्रिया में प्रवेश करने वाले जुझारू और प्रतिस्पर्धी तत्व के कारण अपरिहार्य विकृतियां होती हैं।यदि एक आपराधिक अदालत को न्याय देने में एक प्रभावी साधन बनना है, तो पीठासीन न्यायाधीश को एक दर्शक और केवल रिकॉर्डिंग मशीन नहीं होना चाहिए।उसे 1051 में एक प्रतिभागी बनना होगा।

सच्चाई का पता लगाने के लिए गवाहों से सवाल पूछकर बुद्धिमान सक्रिय रुचि दिखाकर मुकदमा चलाया जाता है।...”

(बल दिया गया)

संयोजन मामलों में उच्च न्यायालय की भूमिका और कर्तव्य

57. हमें यह कहते हुए खेद है कि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पहलुओं की पूरी तरह से अनदेखी की, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय से क्या करने की उम्मीद थी?यदि उच्च न्यायालय ने अभिलेख को देखने के लिए थोड़ा कष्ट उठाया होता, तो तुरंत वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 का सहारा ले सकता था। हम उच्च न्यायालय का ध्यान अध्याय XXVIII (धारा 366 से धारा 371) और अध्याय XXIX (धारा 372 से धारा 394) के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं।धारा 366 से धारा 368 और धारा 386 और धारा 391 के प्रावधान तैयार संदर्भ के लिए यहां उद्धृत किए गए हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“धारा **366**।सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई जाएगी

विश्वास के लिए।— (1) जब सत्र न्यायालय मृत्युदंड की सजा देता है, तो कार्यवाही उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी, और सजा का निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।(2) सजा सुनाने वाला न्यायालय दोषी व्यक्ति को वारंट के तहत जेल हिरासत में देगा।

धारा **367**।आगे की जांच करने या अतिरिक्त जांच करने का निर्देश देने की शक्ति

ले जाने के लिए सबूत।— (1) यदि, जब ऐसी कार्यवाही प्रस्तुत की जाती है, तो उच्च न्यायालय सोचता है कि दोषी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता पर असर डालने वाले किसी भी बिंदु पर आगे की जांच की जानी चाहिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना चाहिए, तो वह ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकता है, या इसे सत्र न्यायालय द्वारा बनाने या लेने का निर्देश दे सकता है।

(2) जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निर्देश नहीं देता है, तब तक दोषी व्यक्ति की उपस्थिति को उस समय समाप्त किया जा सकता है जब ऐसी जांच की जाती है या ऐसा सबूत लिया जाता है।

(3) जब उच्च न्यायालय द्वारा जांच या साक्ष्य (यदि कोई हो) नहीं किया जाता है या नहीं लिया जाता है, तो ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम ऐसे न्यायालय को प्रमाणित किया जाएगा।

धारा **368**।उच्च न्यायालय की सजा या वार्षिक सजा सुनाने की शक्ति

दृढ़ विश्वास।**—** धारा **366** के तहत प्रस्तुत किसी भी मामले में**,** उच्च न्यायालय **-**

((क) सजा को स्वीकार कर सकता है, या कानून द्वारा वारंट कोई अन्य सजा पारित कर सकता है, या

(ख) दोषसिद्धि को निरस्त कर सकता है, और अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहरा सकता है जिसके लिए सत्र न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या उसी या संशोधित आरोप पर नए मुकदमे का आदेश दे सकता है, या

(ग) अभियुक्त व्यक्ति को बरी कर सकता हैः

बशर्ते कि इस धारा के तहत आश्वासन का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अपील करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, या यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई अपील प्रस्तुत की जाती है, जब तक कि ऐसी अपील का निपटारा नहीं किया जाता है।×

×

×

×

धारा 386।अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ।— इस तरह के अवलोकन के बाद

अपीलार्थी या उसके वकील, यदि वह उपस्थित होता है, और लोक अभियोजक, यदि वह उपस्थित होता है, और धारा 377 या धारा 378 के तहत अपील के मामले में, यदि आरोपी उपस्थित होता है, तो अपील न्यायालय, यदि यह मानता है कि हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो अपील को खारिज कर सकता है, या -

(क) बरी किए जाने के आदेश की अपील में, ऐसे आदेश को उलट दें और निर्देश दें कि आगे की जांच की जाए, या आरोपी पर फिर से मुकदमा चलाया जाए या मुकदमा चलाया जाए, जैसा भी मामला हो, या उसे दोषी ठहराया जाए और उसे कानून के अनुसार सजा सुनाई जाए;

(ख) दोषसिद्धि की अपील में-(i) दोषसिद्धि और सजा को उलट देना और अभियुक्त को बरी या आरोपमुक्त करना, या उसे ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा फिर से मुकदमा चलाने का आदेश देना या मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध होना, या

((ii) वाक्य में परिवर्तन करना, वाक्य को बनाए रखना, या

((ग) वाक्यांश में परिवर्तन के साथ या उसके बिना, वाक्य की प्रकृति या विस्तार, या प्रकृति और विस्तार में परिवर्तन करें, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए नहीं;

मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1054

(ग) सजा में वृद्धि के लिए एक अपील में-(i) दंड और सजा को उलट दें और आरोपी को बरी या आरोपमुक्त कर दें या उस पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अदालत द्वारा फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दें, या

((ii) वाक्य को बनाए रखने की विधि में परिवर्तन करें, या

((ग) वाक्य में परिवर्तन के साथ या उसके बिना, वाक्य की प्रकृति या विस्तार, या प्रकृति और विस्तार में परिवर्तन करें, ताकि उसे बढ़ाया या घटाया जा सके।

(घ) किसी अन्य आदेश की अपील में, ऐसे आदेश में परिवर्तन या उलट; (ङ) कोई संशोधन या कोई परिणामी या आनुषंगिक आदेश जो न्यायसंगत या उचित हो सकता हैः

बशर्ते कि सजा को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर न मिला होःबशर्ते कि अपीलीय न्यायालय उस अपराध के लिए, जो उसकी राय में अभियुक्त ने किया है, उस अपराध के लिए अपील के तहत आदेश या सजा पारित करने वाले न्यायालय द्वारा लगाए गए दंड से अधिक दंड का प्रावधान नहीं करेगा।

×

×

×

×

धारा **391**।अपीलीय न्यायालय आगे साक्ष्य ले सकता है या उसे निर्देश दे सकता है।

ले जाने के लिए।— (1) इस अध्याय के तहत किसी भी अपील से निपटने में, अपीलीय न्यायालय, यदि वह अतिरिक्त साक्ष्य को आवश्यक समझता है, तो अपने कारणों को दर्ज करेगा और या तो ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकता है, या इसे मजिस्ट्रेट द्वारा लेने का निर्देश दे सकता है, या जब अपीलीय न्यायालय सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा उच्च न्यायालय हो।

(2) जब सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है, तो वह अपीलीय न्यायालय को ऐसे साक्ष्य को प्रमाणित करेगा और फिर ऐसा न्यायालय अपील का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगा।(3) अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने पर अभियुक्त या उसके वकील को उपस्थित होने का अधिकार होगा।

(4) इस धारा के तहत साक्ष्य लेना अध्याय XXIII के प्रावधानों के अधीन होगा, जैसे कि यह एक जांच थी।"

(बल दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

58. धारा 366 के अनुसार जब सत्र न्यायालय मृत्यु की सजा सुनाता है, तो कार्यवाही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए और मृत्यु की सजा को तब तक निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।धारा 367 तब उच्च न्यायालय की आगे की जांच करने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देने की शक्ति को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ती है।धारा 368, इसके बाद, उच्च न्यायालय की शक्ति को इस तरह से लगाई गई सजा को स्वीकार करने या दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए निर्धारित करती है।उच्च न्यायालय जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, उनमें से एक सीआरपीसी की धारा 368 (सी) के तहत एक है और वह है "आरोपी व्यक्ति को बरी करना"।उल्लेखनीय है कि व्यक्ति को

दोषमुक्त करने की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की ओर से उसकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली कोई ठोस अपील किए बिना भी किया जा सकता है।उस हद तक, अध्याय XXVIII के तहत कार्यवाही जो "कारावास के लिए मौत की सजा प्रस्तुत करने" से संबंधित है, मुकदमे की निरंतरता में एक कार्यवाही है।इस प्रकार ये प्रावधान उच्च न्यायालय को आगे की जांच का निर्देश देने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार देते हैं और उच्च न्यायालय किसी मामले में आरोपी व्यक्ति को बरी भी कर सकता है।अध्याय का दायरा व्यापक है।सी. आर. पी. सी. का अध्याय XXIX "अपील" से संबंधित है।धारा 391 अपीलीय न्यायालय को आगे साक्ष्य लेने या इस तरह के आगे साक्ष्य लेने का निर्देश देने का भी अधिकार देती है।धारा 386 तब अपीलीय न्यायालय की शक्तियों की गणना करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "निर्णय और सजा को उलटने और अभियुक्त को बरी करने या आरोपमुक्त करने की शक्ति शामिल है, या उसे ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा फिर से मुकदमा चलाने का आदेश देना या परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध होना" शामिल है।अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ समान रूप से व्यापक हैं।वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXVIII और XXIX दोनों के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहा था।

59. आम तौर पर, दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक अपील में, अपीलीय अदालत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 के तहत, अपील को खारिज कर सकती है, अगर अदालत की राय है कि हस्तक्षेप के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की शुद्धता को चुनौती देने के लिए उसके सामने आग्रह किए गए सभी आधारों की जांच करने के बाद। अपीलीय न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने स्वयं के एक स्वतंत्र निर्णय पर पहुंचने के उद्देश्य से पूरे रिकॉर्ड की जांच करे कि क्या अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूरी तरह से न्यायोचित है।हालाँकि, स्थिति अलग है जहाँ अपील एक अभियुक्त द्वारा की जाती है जिसे मौत की सजा सुनाई जाती है, ताकि अपील पर विचार करने वाले उच्च न्यायालय के समक्ष, अपील के साथ-साथ, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के तहत मौत की सजा को स्वीकार करने के लिए एक संदर्भ हो। 1055 के विश्वास के लिए एक संदर्भ पर

मृत्युदंड, उच्च न्यायालय से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 और 368 के अनुसार आगे बढ़ने की अपेक्षा की जाती है और इन धाराओं के प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि संदर्भ से निपटने में उच्च न्यायालय का कर्तव्य केवल यह देखना नहीं है कि सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश सही है या नहीं, बल्कि स्वयं मामले की जांच करना और यहां तक कि आगे की जांच या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देना है यदि न्यायालय दोषी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता का पता लगाने के लिए इसे वांछनीय समझता है।यह सच है कि धारा 368 के परंतुक के तहत, जब तक अपील को प्राथमिकता देने के लिए अनुमत अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, या यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई अपील प्रस्तुत की जाती है, जब तक कि ऐसी अपील का निपटारा नहीं किया जाता है, ताकि, यदि कोई अपील किसी दोषी कैदी के नेतृत्व में की जाती है, तो उस अपील का निपटान मृत्यु की सजा को स्वीकार करने वाले संदर्भ में कोई आदेश दिए जाने से पहले किया जाना चाहिए।तथापि, ऐसी अपील के निपटारे में, यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 के तहत अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय को अपने लिए अपील रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए, इस विचार पर पहुंचना चाहिए कि आगे की जांच या अतिरिक्त साक्ष्य लेना वांछनीय है या नहीं, और फिर रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या दोषी कैदी की दोषसिद्धि न्यायसंगत है और मौत की सजा को स्वीकार किया जाना चाहिए।[देखिए:भूपेंद्र सिंह (ऊपर)]60. जुम्मान (ऊपर) में, इस न्यायालय ने वनों की स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में समझाया:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“10. ... लेकिन जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366) के तहत एक संदर्भ दिया जाता है, और जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 423 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386) के तहत अपील का निपटारा किया जाता है, तो एक अंतर होता है और वह यह है कि उच्च न्यायालय को खुद को संतुष्ट करना होता है कि क्या अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मृत्युदंड के उल्लंघन के लिए उचित संदेह से परे मामला बनाया गया है।वास्तव में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही एक पुनर्मूल्यांकन और पूरे तथ्यों और कानून का पुनर्मूल्यांकन है ताकि उच्च न्यायालय को अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध या निर्दोषता के बारे में सामग्री पर संतुष्ट किया जा सके।ऐसा मामला होने के कारण, यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कार्यवाही के सभी पहलुओं पर विचार करे और सत्र न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के अलावा सामग्री पर एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचे।ऐसा करते हुए, उच्च न्यायालय

सत्र न्यायाधीश द्वारा व्यक्त राय से सहायता की जाएगी, लेकिन उपर्युक्त कानून के प्रावधानों के तहत यह उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना है।"

61. राम शंकर सिंह **(**ऊपर**)** में भी इसी सिद्धांत को मान्यता दी गई थी:**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

"12. ... उच्च न्यायालय को इस बात पर भी विचार करना था कि धारा 374 के तहत निर्देश पर क्या आदेश पारित किया जाना चाहिए, और साक्ष्य के मूल्यांकन पर निर्णय लेना था कि क्या अभियुक्तों को दोषी ठहराए जाने के लिए दोषसिद्धि का आदेश न्यायसंगत था और क्या परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मौत की सजा उचित सजा थी।..."

62. मसाल्ती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1964) 8 एस. सी. आर. 133 में, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील पर विचार कर रहा था और उस अपील में, उन व्यक्तियों की ओर से, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, एक बिंदु का आग्रह किया गया था जिसे निचली अदालत के समक्ष लिया गया था और उसके द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष दोहराया नहीं गया था।इस न्यायालय ने कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"11. ...अपीलकर्ताओं को, एक उचित मामले में, इस न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील में उस बिंदु पर विचार करने के लिए कहने की अनुमति हो सकती है; आखिरकार इस चरित्र की आपराधिक कार्यवाही में जहां अपीलकर्ताओं को मौत की सजा दी जाती है, केवल इस आधार पर तथ्य और कानून की प्रासंगिक और भौतिक दलीलों पर विचार करने से इनकार करना उचित नहीं हो सकता है कि उनसे उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह नहीं किया गया था।यदि यह दिखाया जाता है कि याचिकाओं पर वास्तव में उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया था और उस पर विचार नहीं किया गया था, तो निश्चित रूप से पक्षकार इस न्यायालय से उन याचिकाओं पर निर्णय प्राप्त करने के अधिकार के मामले के रूप में हकदार है।लेकिन अन्यथा भी अनुच्छेद 136 के तहत अपीलों में इस तरह की याचिकाओं को उठाने से रोकने के लिए कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।"

63. कुणाल मजूमदार बनाम राजस्थान राज्य, (2012) 9 एस. सी. सी. 320 में, यह

अदालत मौत की सजा पाए एक दोषी के नेतृत्व में एक अपील पर सुनवाई कर रही थी।यह ध्यान दिया गया कि उच्च न्यायालय ने संदर्भ को बहुत ही लापरवाही और कठोर तरीके से केवल यह कहते हुए निपटाया था कि उसमें अपीलार्थी के वकील ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया था।इस न्यायालय ने देखा कि वहाँ बिल्कुल 1057 था

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 (1) के तहत निर्देश में दी गई सजा और दोषसिद्धि के सापेक्ष गुण और अवगुणों पर उस तरीके से विचार नहीं किया जाएगा जिस तरीके से उस पर विचार करने की आवश्यकता थी।इस न्यायालय ने मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हुए इस प्रकार टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"16. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 (1) के तहत मृत्युदंड की सजा पर विचार करने के मामले में, उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 से धारा 371 में निहित प्रावधानों के विशेष संदर्भ के साथ संदर्भ की जांच करने के लिए बाध्य है। सी. आर. पी. सी. की धारा 367 के तहत, जब उच्च न्यायालय के समक्ष निर्देश प्रस्तुत किया जाता है, तो उच्च न्यायालय, यदि यह संतुष्ट करता है कि दोषी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता से संबंधित कोई भी बिंदु पर आगे की जांच की जानी चाहिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना चाहिए, तो वह ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकता है या इसे सत्र न्यायालय द्वारा बनाने या लेने का निर्देश दे सकता है।ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त की उपस्थिति के संबंध में सहायक शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 की उप-धाराओं (2) और (3) के तहत प्रदान की गई हैं। धारा 368 के तहत, धारा 366 के तहत संदर्भ पर विचार करते समय, यह अन्य बातों के साथ-साथ सजा को स्वीकार करने या कानून द्वारा वारंट की गई किसी अन्य सजा को पारित करने का प्रावधान करता है या दोषसिद्धि को रद्द कर सकता है और इसके स्थान पर आरोपी को किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहरा सकता है जिसके लिए सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया हो या उसी या संशोधित आरोप पर नए मुकदमे का आदेश दिया हो।यह अभियुक्त व्यक्ति को भी बरी कर सकता है।धारा 370 के तहत, जब इस तरह के संदर्भ की सुनवाई न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है और यदि वे अपनी राय में विभाजित हैं, तो मामले का निर्णय धारा 392 के

तहत प्रदान किए गए तरीके से किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार मामले को उस न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसे अपनी राय देनी चाहिए और निर्णय या आदेश को उस राय का पालन करना चाहिए।यहां फिर से, धारा 392 के परंतुक के तहत, यह निर्धारित किया गया है कि यदि पीठ का गठन करने वाले न्यायाधीशों में से एक या जहां अपील किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है, तो उनमें से कोई भी, यदि आवश्यक हो, तो न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा दिए जाने वाले निर्णय के लिए अपील की फिर से सुनवाई के लिए निर्देश दे।

17. जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 (1) के तहत एक संदर्भ पर विचार करते समय उच्च न्यायालय पर ऐसी विशेष और भारी जिम्मेदारी थोपी गई है, तो हम यह जानकर हैरान हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 (1) के तहत 2007 के आदेश [आपराधिक हत्या संदर्भ संख्या 1] में, 11-7 पर निर्णय लिया गया है -

2007 (राज)] इसमें आक्षेप करते हुए, खंड पीठ ने केवल इस आशय को दर्ज किया कि अपीलार्थी के वकील ने आई. पी. सी. की धारा 376/511 के तहत अपराध के लिए दी गई सजा को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हुए आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आने वाले अपराध के लिए मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए सहानुभूति का अनुरोध किया और कहा कि विद्वान लोक अभियोजक की ओर से कोई विरोध नहीं था।डिवीजन बेंच ने उस एकमात्र आधार पर और केवल यह कहते हुए कि अपीलार्थी के हाथों पीड़ित पर गंभीर प्रकृति के बल का कोई उपयोग नहीं किया गया था और हत्या के अपराध को क्रूर या अमानवीय नहीं माना जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप मौत की सजा को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास के रूप में बदला जा सकता है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 368 से धारा 370 और 392 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 (1) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की जहमत नहीं उठाई और इस तरह, हमारी राय में, संदर्भ का निर्णय करते समय अपनी जिम्मेदारी को उस तरीके से कम कर दिया जिस तरह से दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इसे अन्यथा तय किया जाना चाहिए था। हम महसूस करते हैं कि कम कहा जाना उस सरसरी तरीके पर टिप्पणी करते समय बेहतर है जिसमें खंड पीठ द्वारा धारा 366 (1) के तहत संदर्भ पर विचार करते हुए विवादित निर्णय [धारा 366 (1) सीआरपीसी के तहत 2007 का आपराधिक हत्या संदर्भ संख्या 1, जो 11-7-2007 (राज) पर तय किया गया था] पारित करते समय निर्णय सुनाया गया था।18. हालाँकि हम यह बताने और दर्ज करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 (1) के तहत दिए गए संदर्भ में, उच्च न्यायालय द्वारा केवल दोषी के वकील या राज्य के वकील द्वारा दी गई किसी भी रियायत पर भरोसा करके संदर्भ की प्रक्रिया को शॉर्ट-सर्किट करने का कोई सवाल ही नहीं है।उच्च न्यायालय पर यह कर्तव्य डाला गया है कि वह अपराध करने की प्रकृति और तरीके, यदि कोई हो तो पुरुष कारण, निचली अदालत द्वारा उल्लिखित पीड़ित की दुर्दशा, जिस शैतानी तरीके से अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया था, पीड़ित के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समाज पर इसके दुष्प्रभाव, लोक हित के प्रति अपराधी की मानसिकता, अपराध करने के तुरंत बाद दोषी का आचरण और उसके बाद, अपराधी का पिछला इतिहास, अपराध की भयावहता और पीड़ित के आश्रितों या संरक्षकों पर इसके परिणामों की जांच करे।1059 पर बहुत व्यापक रूप से विचार किया जाना चाहिए।

मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 1060

यह सुनिश्चित करने के लिए कि संदर्भ का अंतिम परिणाम शांतिप्रिय नागरिकों के मन में विश्वास पैदा करेगा और दूसरों को ऐसे अपराधों में लिप्त होने से रोकने के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करने के उद्देश्य को भी प्राप्त करेगा, उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ के साथ व्यवहार किया गया।

(बल दिया गया)

फेयर ट्रेल की अवधारणा

64. सभी निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक रूप से कानूनी रूप से मान्य हैं, लेकिन क्या इसके विपरीत आवश्यक रूप से सच है?फिर निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा की उत्पत्ति क्या है?एक निष्पक्ष मुकदमे की अवधारणा की एक बहुत ही प्रभावशाली वंशावली है, जो इतिहास में निहित है, संविधान में निहित है, धार्मिक दर्शन और न्यायिक सिद्धांतों द्वारा पवित्र है और एक आपराधिक मुकदमे के पाठ्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से क़ानून में सन्निहित है।इसकी व्यापक विशेषताओं और अवयवों को, समय के साथ, अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों में मूर्त रूप दिया गया है, भले ही ऐसे अस्पष्ट क्षेत्र हैं, जो आगे के कानूनी विचार और अनुसंधान की मांग करते हैं।

65. सत्य एक पोषित सिद्धांत है और भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का मार्गदर्शक सितारा है।न्याय के लिए सत्य की जीत होनी चाहिए।सत्य न्याय की आत्मा है।आपराधिक न्याय प्रणाली का एकमात्र विचार यह देखना है कि न्याय किया जाए।न्याय तब किया जाएगा जब किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा और दोषी व्यक्ति को मुक्त नहीं होने दिया जाएगा।

66. आपराधिक न्याय के वितरण के लिए, भारत सामान्य कानून की अभियोगात्मक या प्रतिकूल प्रणाली का पालन करता है। अभियोगात्मक या प्रतिकूल प्रणाली में अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है; अभियोजन और बचाव प्रत्येक अपना मामला रखते हैं; न्यायाधीश एक निष्पक्ष अंपायर के रूप में कार्य करता है और एक तटस्थ अंपायर के रूप में कार्य करते हुए देखता है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम है या नहीं।

67. स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अनिवार्यता है।यदि आपराधिक मुकदमा स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, तो न्यायाधीश की न्यायिक निष्पक्षता और न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास हिल जाएगा।निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करना आरोपी के साथ उतना ही अन्याय है जितना कि पीड़ित और समाज के साथ।किसी भी मुकदमे को निष्पक्ष मुकदमे के रूप में तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि मुकदमे का संचालन करने वाला एक निष्पक्ष न्यायाधीश, एक ईमानदार, सक्षम और निष्पक्ष बचाव वकील और समान रूप से ईमानदार, सक्षम और निष्पक्ष लोक अभियोजक न हो।एक निष्पक्ष सुनवाई में अनिवार्य रूप से अभियोजक को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए निष्पक्ष और उचित अवसर और अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर शामिल है।

68. सत्य तथ्यों का पता लगाने के बाद न्याय के वितरण में एक न्यायाधीश की भूमिका निस्संदेह बहुत कठिन है।सत्य को उजागर करने की पवित्र प्रक्रिया में ताकि पक्षकारों के बीच न्याय प्रदान करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, न्यायाधीश किसी भी मामले की सुनवाई की प्रगति के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं से खुद को बेपरवाह और अनजान नहीं रख सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे बहुत सतर्क, सतर्क, निष्पक्ष और निष्पक्ष रहना होगा, और यह धारणा भी नहीं देनी होगी कि वह अपने व्यक्तिगत विश्वासों या किसी एक या दूसरे पक्ष के पक्ष में विचारों के कारण पक्षपाती या पूर्वाग्रहपूर्ण है।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि न्यायाधीश केवल अपनी आँखें बंद कर लेगा और एक मूक दर्शक बन जाएगा, एक रोबोट या रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करेगा ताकि केवल पक्षकारों द्वारा दिए गए सामान को वितरित किया जा सके।

69. न्यायिक सुधारों पर मलिमथ समिति ने सच्चाई की खोज करने के लिए न्यायालयों के सर्वोच्च कर्तव्य पर चर्चा की।समिति की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(क) भारतीय लोकाचार सत्य को सर्वोच्च महत्व देता है।आदर्श वाक्य "सत्यमेव जयते" (केवल सत्य ही सफल होता है) हमारे राष्ट्रीय प्रतीक "अशोक स्तम्भ" में अंकित है।हमारे महाकाव्य सत्य के गुण की प्रशंसा करते हैं।

(ख) आम आदमी के लिए सत्य और न्याय पर्यायवाची हैं।इसलिए जब सच्चाई विफल हो जाती है, तो न्याय विफल हो जाता है। जो लोग जानते हैं कि बरी किया गया आरोपी वास्तव में अक्षम था, वे व्यवस्था में विश्वास खो देते हैं।

(ग) व्यवहार में हालांकि हम यह मानते हैं कि न्यायाधीश, अपनी तटस्थता प्रदर्शित करने की अपनी चिंता में निष्क्रिय रहने का विकल्प चुनता है और सच अक्सर एक दुर्घटना बन जाता है।

(घ) सत्य भारत का पोषित आदर्श और लोकाचार होने के कारण, सत्य की खोज न्याय प्रणाली का मार्गदर्शक सितारा होना चाहिए।न्याय के लिए सत्य की जीत होनी चाहिए।यह सत्य है जिसे निर्दोष की रक्षा करनी चाहिए और यह सत्य है जो दोषियों को दंडित करने का आधार होना चाहिए।सत्य न्याय की आत्मा है।इसलिए, अदालतों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए सच्चाई आदर्श बननी चाहिए।

(ई) कई देश जिनके पास जांच का मॉडल है, उन्होंने अपने संसदीय अधिनियमों में मामले में सच्चाई का पता लगाने का कर्तव्य अंकित किया है।जर्मनी में तथाकथित 'मजना चार्टा' की धारा 139 का उल्लंघन 1061 है।

सक्रिय रूप से सत्य की खोज करने का न्यायाधीशों का कर्तव्य एक प्रक्रियात्मक त्रुटि को उजागर करेगा जो अपील के लिए आधार प्रदान कर सकता है।(च) न्यायालयों के लिए सत्य की खोज से बेहतर या उच्चतर कोई आदर्श नहीं हो सकता है।

70. इस न्यायालय ने न्यायाधीशों द्वारा निभाई गई निष्क्रिय भूमिका की निंदा की है और न्याय देने के लिए सच्चाई को साबित करने और सच्चाई को हताहत होने से रोकने के लिए कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एक न्यायाधीश के महत्व और कानूनी कर्तव्य पर जोर दिया है।एक न्यायाधीश निष्पक्षता के साथ कार्य करने के लिए भी कर्तव्यबद्ध है और इससे पहले कि वह पक्षकारों के बीच मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए कोई राय दे या बैठता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एल. आई. एस. के किसी भी पक्ष के खिलाफ या उसके पक्ष में कोई पूर्वाग्रह नहीं है।एक न्यायाधीश के लिए इस कर्तव्य का उचित रूप से निर्वहन करने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा मौजूद है और इसमें एक न्यायाधीश की क्षमता और कर्तव्य शामिल है कि वह बाहरी कारकों के प्रवाह के बिना प्रत्येक मामले को एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और कानून के अनुप्रयोग के अनुसार तय करे।
71. यदि न्यायालयों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से न्याय प्रदान करना है, तो पीठासीन न्यायाधीश अपने आस-पास होने वाली विभिन्न घटनाओं, विशेष रूप से अपने द्वारा चलाए जा रहे किसी विशेष मामले के बारे में पूरी तरह से अनजान मूक दर्शक बने रहने का आदेश नहीं दे सकता है।निष्पक्ष सुनवाई तभी संभव है जब अदालत सक्रिय रुचि लेती है और सभी प्रासंगिक जानकारी और आवश्यक सामग्री प्राप्त करती है ताकि दोनों पक्षों को पूरी निष्पक्षता और निष्पक्षता के साथ न्याय देने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सच्चाई का पता लगाया जा सके।

72. राम चंदर (ऊपर) में, एक आपराधिक मुकदमे में पीठासीन न्यायाधीश के बारे में बोलते हुए, न्यायमूर्ति चिन्नाप्पा रेड्डी ने कहा कि यदि एक आपराधिक अदालत को न्याय देने में एक प्रभावी साधन बनना है, तो पीठासीन न्यायाधीश को एक दर्शक और केवल रिकॉर्डिंग मशीन नहीं होना चाहिए।उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए गवाहों से सवाल पूछकर बुद्धिमान सक्रिय रुचि दिखाकर मुकदमे में एक प्रतिभागी बनना चाहिए।विद्वान।

न्यायाधीश ने सत्र न्यायाधीश, नेल्लोर बनाम इंथा रमन्ना के एक अंश को पुनः प्रस्तुत किया

रेड्डी**, 1972 Cri.L.J. 1485,** जो इस प्रकार हैः**—**

“प्रत्येक आपराधिक मुकदमा खोज की एक यात्रा है जिसमें सत्य की खोज होती है।एक पीठासीन न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह सच्चाई की खोज करने और न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने लिए खुले हर रास्ते का पता लगाए।उस उद्देश्य के लिए वह धारा 165 द्वारा स्पष्ट रूप से निवेशित है।

गवाहों से प्रश्न पूछने के अधिकार के साथ साक्ष्य अधिनियम।वास्तव में एक न्यायाधीश को दिया गया अधिकार इतना व्यापक है कि वह किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी गवाह से, या किसी भी तथ्य के बारे में पक्षकारों से, प्रासंगिक या अप्रासंगिक, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 (2) अदालत को किसी मामले में पुलिस-डायरी भेजने और मुकदमे में सहायता के लिए उनका उपयोग करने में सक्षम बनाती है।अभियोजन मजिस्ट्रेट की कार्यवाहियों के अभिलेख पर भी सत्र न्यायाधीश द्वारा विचार किया जा सकता है ताकि उसे मुकदमे में और सहायता मिल सके।"

73. सभी पूर्वगामी कारणों से, हमारे पास उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार करने और मामले को सीआरपीसी की धारा 366 के तहत संदर्भ पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों के मौखिक साक्ष्य से सामने आने वाले भौतिक चूक के रूप में प्रमुख विरोधाभासों को साबित नहीं करने में बचाव पक्ष की ओर से गंभीर खामियों को ध्यान में रखते हुए।

74. अगर कोई हमसे सवाल पूछे, "इस फैसले का अनुपात क्या है?” क्लेरेंस डारो के शब्दों में इसका उत्तर बहुत सरल और स्पष्ट होगा।

“न्याय का अदालत कक्ष में जो होता है उससे कोई लेना-देना नहीं है; न्याय वह है जो अदालत कक्ष से निकलता है।"

75. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को 2017 की मृत्यु संदर्भ संख्या 4 और 2017 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 358 पर पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है।2017 की मृत्यु संदर्भ संख्या 4 और 2017 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 358 को कानून के अनुसार उच्च न्यायालय के पुनर्विचार के लिए बहाल कर दिया गया है।

76. अपीलार्थी पिछले नौ साल से अधिक समय से जेल में है।ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय में पुनर्स्थापित किए जाने पर ऊपर निर्दिष्ट मृत्यु संदर्भ को शीघ्रता से सुनवाई के लिए लिया जाएगा।उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि वे एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आपराधिक अपील के साथ मृत्यु संदर्भ को अधिसूचित करें जिसका वह गठन कर सकते हैं।हम मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीशों से भी अनुरोध करते हैं कि वे प्राथमिकता दें और कानून के अनुसार जल्द से जल्द इसका निपटारा करें।

1063

मुन्ना पांडे बनाम बिहार राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

77. चूंकि अपीलार्थी दोषी पिछले नौ साल से अधिक समय से जेल में है, इसलिए उसका परिवार गंभीर संकट में हो सकता है। हो सकता है कि वह अपनी पसंद के वकील को नियुक्त करने की स्थिति में न हो।हो सकता है कि वह यह समझने की स्थिति में न हो कि इस फैसले में क्या कहा गया है।ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय अपीलार्थी की ओर से पेश होने और न्यायालय की सहायता करने के लिए एक अनुभवी आपराधिक पक्ष के वकील से अनुरोध कर सकता है।

78. रजिस्ट्री इस निर्णय की एक-एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों को भेजेगी और प्रत्येक उच्च न्यायालय से इसे अपनी संबंधित जिला न्यायपालिका में प्रसारित करने का अनुरोध करेगी।

79. अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे